



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 1990/अग्रहायण 29, 1912
No. 552] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 1990/AGRAHAYANA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1990

दान-कर

सा.का.नि. 990 (अ).—केन्द्रीय सरकार, दान-कर
अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 44 के
स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, घोषित
करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस अधिनियम के
प्रयोजनों के लिए एक व्यक्तिकारी देश होगा।

[अधिसूचना सं. 8788/फा.सं. 501/2/74 एफटीडी]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th December, 1990

GIFT TAX

G.S.R. 990(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 44 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Government hereby declares the United States of America to be a reciprocating country for the purposes of that Act.

[Notification No. 8788/F. No. 501/2/74-I-TD]

सा.का.नि. 991 (अ). :—केन्द्रीय सरकार, धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क के

पण्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्तिकारी देश होगा।

[अधिसूचना नं. 8787/फा.सं. 501/2/74-एफ टी डी]

WEALTH TAX

G.S.R. 991(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 44A of the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby declares the United States of America to be a reciprocating country for the purposes of that Act.

[Notification No. 8787/F. No. 501/2/74-FTD]

आय-कर

सा.का.नि. 992 (अ) :—दोहरे कराधान का अपवर्जन करने के लिए और आय पर करों की बाबत राज-वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच उभरे उपायबद्ध कन्वेंशन, उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में उक्त कन्वेंशन को प्रवृत्त करने के लिए अपने कानूनों के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा कर दोनों सविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे की अधिसूचना के पश्चात् 18-12-1990 को प्रवृत्त किया गया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

यह और कि, केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) की धारा 44-क (ख) और दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 44(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह भी निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 के उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपाबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार
के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक तथा अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा में, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

सामान्य क्षेत्र

1. इस अभिसमय में जब तक कि अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों सविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

2. यह अभिसमय इस समय अथवा इसके पश्चात् :

(क) दोनों में से किसी भी सविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा : अथवा

(ख) सविदाकारी राज्यों के बीच अन्य किसी करार द्वारा स्वीकृत किसी अपवर्जन छूट, कटौती, क्रेडिट, अथवा किसी प्रकार की अन्य छूट को किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं करेगा।

3. इस अभिसमय के पैरा 4 के अलावा किसी भी उपबन्ध के होते हुए भी, कोई भी सविदाकारी राज्य (अनुच्छेद 4) निवास (के तहत यथा-निर्धारित) अपने निवासियों पर कर लगा सकता है, और नागरिकता के कारण अपने नागरिकों पर उसी प्रकार कर लगा सकता है जैसे कि यह अभिसमय प्रवृत्त ही नहीं हुआ हो। इस प्रयोजनार्थ, "नागरिक" शब्द में वह भूतपूर्व नागरिक भी शामिल होगा जिसकी नागरिकता की समाप्ति का कोई मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन कर परिहार करना था, लेकिन उसे ऐसी समाप्ति के 10 वर्ष बाद तक की अवधि के लिए ही शामिल किया जाएगा।

4. पैरा 3 के उपबन्ध निम्नलिखित प्रसूचिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे :

(क) अनुच्छेद 9 के पैरा 2 (सहबद्ध उद्यम) के तहत अनुच्छेद 20 के पैरा 2 तथा 6 (निजी पेंशन, वापिकियों, निर्वाह-व्यय और बाल-सहायता) के तहत और अनुच्छेद 25 (दोहरे कराधान में राहत), 26 (भेदभाव-रहित) और 27 (परस्पर करार प्रक्रिया) के तहत एक सविदाकारी राज्य द्वारा प्रदत्त लाभों पर; और

(ख) अनुच्छेद 19 (सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन), 21 (विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त भुगतान), 22 (प्राध्यापकों, अध्यापकों और शोध छात्रों द्वारा प्राप्त भुगतान) और 29 (राजनयिक अभिकर्तियों और कौमत्तीय अधिकारियों) के तहत एक संविदाकारी राज्य द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदत्त लाभों पर, जो न तो उस राज्य के नागरिक हैं अथवा न ही उसके आप्रवासी हैं।

अनुच्छेद-2

सम्मिलित कर

1. मौजूदा कर, जिन पर यह अभिसमय लागू होगा, वे ये हैं:—

(क) संयुक्त राज्य अमरीका में, आन्तरिक राजस्व कोड द्वारा लगाए गए संघीय आमदनी कर (किन्तु संचित आयकर वैयक्तिक नियंत्रक कंपनी कर और सामाजिक सुरक्षा करों को छोड़कर), और विदेशी बीमाकर्तियों को प्रदत्त बीमा प्रीमियमों पर और निजी संस्थाओं पर लगाए गए उत्पादन शुल्क संबंधी कर (जिन्हें यहाँ इसके पश्चात् “संयुक्त राज्य अमरीका कर” के रूप में कहा जाएगा); लेकिन इस प्रावधान के साथ कि यह अभिसमय विदेशी बीमाकर्तियों को प्रदत्त बीमा प्रीमियमों पर लगाए गए उत्पादन शुल्क संबंधी करों पर केवल उसी सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक ऐसे प्रीमियमों द्वारा समाविष्ट जीवियों का बीमा उस व्यक्ति के पास पुनः नहीं कराया जाता है जो इन करों पर लागू होने वाले इस अभिसमय अथवा अन्य किसी अभिसमय के अन्तर्गत ऐसे करों से छूट का हकदार नहीं है; और

(ख) भारत में:

(1) आयकर तथा उस पर लगाए गए किसी भी अधिभार पर, लेकिन इसमें कंपनियों की अविश्रुत आय पर आयकर अधिनियम के तहत लगाया गया आयकर शामिल नहीं है; और

(2) अधिभार:

(जिस इसके बाद “भारतीय कर” कहा गया है)। उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित करों में उपर्युक्त करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल-बूझ के सिलसिले में संदेय कोई भी रकम शामिल नहीं होगी अथवा वह रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में दण्ड के रूप में लगाई गई हो।

2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा गारन्टी इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् मौजूदा करों के अतिरिक्त, अथवा उनके स्थान पर, लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के मध्य प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके

अपने-अपने कराधान कानूनों में तथा इस अभिसमय के लागू होने से संबंधित सरकारी तौर पर प्रकाशित किसी भी सामग्री के संबंध में किए गए हों।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस अभिसमय में, जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है—भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है—राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिसके बारे में भारत की भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर-राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं;

(ख) “संयुक्त राज्य अमरीका” शब्द से अभिप्रेत है—जब एक भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है संयुक्त राज्य अमरीका का राज्य क्षेत्र जिसमें यह भी शामिल है—राज्य क्षेत्रीय समुद्र जिस पर संयुक्त राज्य अमरीका के कर से संबंधित कानून लागू होता है, राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे समस्त क्षेत्र जिसमें उसका समुद्रतल तथा अवस्था भी शामिल है, जिस पर संयुक्त राज्य अमरीका अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्राधिकार रखता है तथा जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका के कर से संबंधित कानून प्रवृत्त हैं;

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” तथा “दूसरा संविदाकारी राज्य” पदों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा संयुक्त राज्य अमरीका अभिप्रेत हैं;

(घ) “कर” शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा संयुक्त राज्य अमरीका कर अभिप्रेत हैं;

(ङ) “व्यक्ति” शब्द में कोई व्यक्ति, कोई संपदा, कोई न्यास, कोई भागीदारी, कोई कंपनी, व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, अथवा अन्य कर योग्य सत्ता शामिल है;

(च) “कम्पनी” शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर-प्रयोजनों के लिए एक कम्पनी अथवा एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(छ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” और “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत हैं;

(ज) “सक्षम प्राधिकारी” पद से अभिप्रेत है—भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केन्द्रीय सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में, वित्त मन्त्रि अथवा उनका प्रतिनिधि;

(ज) “राष्ट्रिक” शब्द का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसे एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता अथवा नागरिकता प्राप्त है;

भारत में प्रयुक्त कानूनों में इस तरह की हैसियत प्राप्त हो :

(अ) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है— किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब उक्त जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो; और

(ट) भारतीय कर से संबंधित कराधेय वर्ष पद से आयाकर अधिनियम, 1961 में यथा-परिभाषित “पूर्ववर्ती वर्ष” अभिप्रेत है।

2. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्दावली का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुई हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 27 (परस्पर करार प्रक्रिया) के उपबंधों के अनुसार कोई एक ही अर्थ मानने के लिए सहमत न हों, तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर ये अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद-4

निवास

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” पद से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, नागरिकता, प्रबंध-स्थान, संस्थापन-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य कसौटी के कारण वहाँ पर कर लगाया जा सकता है, तथापि शर्त यह है कि—

(क) इस पद में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो उस राज्य में केवल स्रोत से प्राप्त आय के संबंध में उस राज्य में कर का दायी है; और

(ख) यदि आय भागीदारी, संपदा, अथवा न्यास से प्राप्त होती है अथवा मिलती है, तो यह पद उस सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक ऐसी भागीदारी, संपदा, अथवा न्यास द्वारा अर्जित आय पर एक निवासी की आय के रूप में उस राज्य में कर लगेगा और यह कर या तो उसके अपने हाथ में प्राप्त आय पर लगेगा या उसके भागीदारों अथवा हिताधिकारियों के हाथों में प्राप्त आय पर लगेगा।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसकी

हैसियत का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाएगा :

(क) वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसका स्थायी घर हो; यदि उनका दोनों राज्यों में स्थायी घर हो, तो उसे उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठ हों (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) :

(ख) यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र हो, अथवा यदि उसका किसी भी राज्य में स्थायी घर नहीं हो, तो उसे उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिस राज्य में वह नियमित रूप से रह रहा हो;

(ग) यदि वह दोनों राज्यों में नियमित रूप से रह रहा हो अथवा वह किसी भी राज्य में नियमित रूप से नहीं रह रहा हो तो उसे उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस मामले को सुलझाएंगे।

3. यदि पैराग्राफ 1 के कारण कोई कंपनी दोनों संविदाकारी राज्यों की निवासी है तो ऐसी कंपनी को अनुच्छेद 10 (लाभांश) के पैरा 2, अनुच्छेद 26 (भेदभाव रहित), अनुच्छेद 27 (परस्पर करार प्रक्रिया), अनुच्छेद 28 (सूचना तथा प्रशासनिक सहायता का आदान-प्रदान) और अनुच्छेद 30 (प्रवृत्त होना) के प्रयोजनों के अलावा इस अभिसमय के विषय-क्षेत्र से बाहर समझा जाएगा।

4. यदि पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति अथवा कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस मामले को हल करेंगे और ऐसे व्यक्ति पर इस अभिसमय के लागू किए जाने का तरीका निर्धारित करेंगे।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय प्रयोजनार्थ “स्थायी संस्थापन” पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

- (ड) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, क्षेत्र अथवा गैस या कोई कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई भण्डारण जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो;
- (ज) कोई फार्म, बगीचा अथवा अन्य स्थान जहाँ पर कृषि, बानिकी, पौधे उगाने अथवा उनसे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं;
- (झ) कोई भण्डार अथवा बिक्री केन्द्र के रूप में प्रयुक्त परिसर;
- (ञ) कोई संस्थापना अथवा संरचना जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा उपयोग के लिए किया जाता हो, किन्तु केवल उस स्थिति में जब उसका इस्तेमाल किन्हीं 12 महीनों की अवधि में 120 दिन से अधिक समय तक किया गया हो,
- (ट) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, संस्थापना अथवा ऐम्बरवली प्रोजेक्ट अथवा उसके संबंध में पर्यवेक्षी गतिविधियाँ, जहाँ ऐसा स्थल, प्रोजेक्ट और गतिविधियाँ (अन्य ऐसे स्थलों, प्रोजेक्टों अथवा गतिविधियों, यदि कोई हों, सहित) किन्हीं 12 महीनों की अवधि में 120 दिन से अधिक समय तक जारी रहती हैं;
- (ठ) कर्मचारियों अथवा अन्य कामिकों के जरिए किसी उद्यम द्वारा एक सविदाकारी राज्य के भीतर अनुच्छेद 12 (सम्मिलित सेवाओं हेतु रायल्टियाँ और फीस) में यथा परिभाषित सम्मिलित सेवाओं से भिन्न सेवाओं को प्रदान किया जाना लेकिन केवल तभी यदि :
- (i) उस प्रकार की गतिविधियाँ किन्हीं बारह महीनों की अवधि के भीतर कुल 90 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस राज्य के भीतर जारी रहती हैं; अथवा
- (ii) उस राज्य के भीतर किसी संबंधित उद्यम के लिए सेवाओं का निष्पादन किया जाता है [अनुच्छेद 9 के पैरा 1 के अर्थ के अंतर्गत (सहवृद्ध उद्यम)]

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होने हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद से निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक का शामिल होना माना जाएगा :

- (क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के भण्डारण, प्रदर्शन अथवा यदा कदा सुपुर्वगी के प्रयोजनार्थ माल सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
- (ख) माल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा यदा कदा सुपुर्वगी के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल

अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

- (ग) मात्र किसी अन्य उद्यम द्वारा ससाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- (घ) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं की मात्र खरीद करने अथवा उसके बारे में सूचना एकत्र करने के लिए व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- (ङ) उस उद्यम के लिए मात्र विज्ञापन, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा अन्य प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहाँ पर कोई स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की तरफ से किसी सविदाकारी राज्य में कार्य करता हो, उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित सविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि :—

- (क) यदि उसे उस उद्यम की तरफ से उस प्रथमोल्लिखित राज्य में ठेकों को सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह आदतन ऐसे ठेके सम्पन्न करता हो जब तक कि इसके कार्यकलाप, यदि उन्हें कारोबार के किसी निश्चित स्थान पर सम्पन्न किया गया हो, पैराग्राफ 3 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित नहीं हों, जिसके द्वारा कारोबार का यह निश्चित स्थान उस पैराग्राफ के उपबंधों के तहत एक स्थायी संस्थापन नहीं बनेगा;
- (ख) उसके पास इस तरह का कोई प्राधिकार नहीं हो किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो जिसमें से वह नियमित रूप से इस उद्यम की तरफ से माल अथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी करता हो, और उस उद्यम की ओर से उस राज्य में चलाए गए कुछ अतिरिक्त कार्यकलापों से माल अथवा पण्य वस्तुओं की बिक्री में सहयोग मिला हो; अथवा
- (ग) वह उस प्रथमोल्लिखित राज्य में आदतन आदेश प्राप्त करता हो, जो पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम के लिए हो ।

5. एक सविदाकारी राज्य के उद्यम को किसी दूसरे सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना मात्र इस कारण नहीं माना जाएगा कि वह किसी दवाय, सामान्य

कमीशन एजेंट अथवा किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट की मार्फत उस दूसरे राज्य में व्यापार चलाता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार की सामान्य प्रश्रिया में कार्य करते हैं। तथापि, यदि ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप उस उद्यम की ओर से पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः समर्पित हैं और एजेंट तथा उद्यम के मध्य संव्यवहार कड़ी शर्तों के तहत नहीं होता है तो उसे इस पैरे के अर्थ के अन्तर्गत स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएगा।

6. इस तथ्य से कि कोई कंपनी जो किसी सविदाकारी राज्य की निवासी है किसी ऐसी कंपनी पर नियंत्रण रखती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे सविदाकारी राज्य की निवासी हो अथवा जो दूसरे सविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार चलाती हो, दोनों में से किसी भी कंपनी को दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन का दर्जा नहीं देना है।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति (वास्तविक संपत्ति) से आय

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (वास्तविक संपत्ति) से प्राप्त आय पर, जिसमें कृषि अथवा वनोद्योग से प्राप्त आय भी शामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस सविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार संबंधी लाभ

1. किसी सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी सविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगाया जा सकेगा जो —

(क) उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए हों; (ख) उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेचे जाने वाले एक-समान अथवा उसमें मिलते-जुलते किस्म के माल अथवा पण्य वस्तुओं की दूसरे राज्य में बिक्री; अथवा (ग) उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से दूसरे राज्य में चलाए जा रहे एक-समान अथवा उसमें मिलते-जुलते कारोबार संबंधी कार्यकलाप।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो तो प्रत्येक सविदाकारी राज्य में ऐसे लाभों को उस स्थायी संस्थापन के लाभ समझा जाएगा जो उसे उस स्थिति में प्राप्त होने की अपेक्षा रहती जब वह एक-समान अथवा उसमें मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उसमें मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और स्वतंत्र उद्यम होता और उस उद्यम जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है, के साथ और अन्य नियंत्रणकारी, नियंत्रित उद्यमों अथवा उसी प्रकार के सामान्य नियंत्रणाधीन उद्यम जैसा कि वह उद्यम है, के साथ पूर्णतः निष्पक्ष रूप से कारोबार करता। किसी भी दशा में, यदि किसी स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों का सही रकम का निर्धारण नहीं किया जा सकता है अथवा उसके निर्धारण में असाधारण कठिनाइयां आती हैं, तो स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों के आकलन यथोचित आधार पर किए जाएंगे। तथापि, जो आकलन अपनाए जाएंगे वे ऐसे होंगे जिनमें परिणाम इस अनुच्छेद में निर्हित सिद्धान्तों के अनुसार प्राप्त हो।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन खर्चों को कटौतियों के रूप में अनुमति दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिसमें इस प्रकार के किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च, अनुसंधान तथा विकास खर्च, ब्याज और अन्य खर्चों का यथोचित आवंटन जिन्हें पूर्णतः उस उद्यम (अथवा उसके उस भाग, जिसमें स्थायी संस्थापन भी शामिल है) के प्रयोजनों के लिए व्यय किया गया हो, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र और उन खर्चों उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों और उनकी परिसीमाओं के अधधीन हों। तथापि, रायल्टियों, फीमों के रूप में उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को स्थायी संस्थापन द्वारा प्रदत्त (वास्तविक खर्चों की प्रति-प्रति से भिन्न) रकमों, यदि कोई हों, के संबंध में अथवा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के बदले में, अथवा विनिष्ट सेवा-निष्पादन अथवा प्रबंध व्यवस्था के सिलसिले में कमीशन अथवा अन्य प्रभारों, अथवा बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में इसी प्रकार की अन्य अदायगी के संबंध में ऐसी किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसी प्रकार, किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, रायल्टियों, फीसों अथवा पेयेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में, अथवा विनिष्पन्न सेवा-निष्पादन या प्रबंध व्यवस्था के मिलाने में कमीशन अथवा अन्य प्रभागों के रूप में, अथवा वैकल्पिक उद्यम के मामलों के अलावा, उस उद्यम के मुख्य कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को दिए गए धन पर व्याज के रूप में की गई इसी प्रकार की अन्य अदायगियों के रूप में उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा किसी कार्यालय में से किसी अन्य को उस स्थायी संस्थापन द्वारा प्रभारित राशियों (वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति से भिन्न) का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा।

4. कोई भी ऐसा लाभ मात्र इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन का प्राप्ति हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

5. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, इस अनुच्छेद के पैरा 1(क) में यथा-उपबंधित स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों में वे लाभ भी शामिल हैं जो उस संस्थापन की परिसंपत्तियों तथा कार्यकलापों से प्राप्त हुए हैं और उन्हें तब तक वर्णानुवर्ण इसी तरीके से निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

6. जहां पर लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां पर उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

7. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "कारोबार संबंधी लाभों" पद का अभिप्राय उस आय से है जो किसी व्यापार अथवा कारोबार से प्राप्त हुई हो, जिसमें अनुच्छेद 12 (शामिल की गई सेवाओं के लिए रायल्टियों और फीस) में यथा-परिभाषित शामिल सेवाओं से भिन्न सेवाओं से प्राप्त आय शामिल है और वह आय भी शामिल हो जो अनुच्छेद 12 में शामिल की गई सेवाओं के लिए रायल्टियां और फीस के पैरा 3(ख) में वर्णित संपत्ति से भिन्न वास्तविक व्यक्तिगत संपत्ति के किराए से प्राप्त आय भी शामिल है।

अनुच्छेद 8

नौवहन एवं वायु परिवहन

1. किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों का मापन उन लाभों से है जो निम्नलिखित सहित जलयानों

अथवा वायुयानों के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा चार्टरों द्वारा यात्रियों, मेल, पशुओं माल को क्रमशः समुद्र अथवा हवाई मार्ग से लाने-जे-जाने से संबंधित पैरा 1 में वर्णित किसी उद्यम द्वारा प्राप्त किए गए हों—

- (क) अन्य उद्यमियों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री;
- (ख) ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित अन्य कार्यकलाप; और
- (ग) ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित किसी कार्यकलाप के संबंध में जलयानों अथवा वायुयान का प्रारम्भिक किराया।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के संबंध में प्रयुक्त आधानों (ट्रेलरों, नौकाओं और आधानों के परिवहन के लिए सम्बद्ध उपकरण सहित) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए से राजत, पैरा 1 में वर्णित किसी संविदाकारी राज्य के उद्यमों के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

4. पैरा 1 और 3 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार, अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर प्राप्त व्याज को ऐसे पोतों अथवा एंशरकाफ्ट के परिचालन से व्युत्पन्न लाभों के रूप में समझा जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध (व्याज) में ऐसे व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

6. किसी उद्यम के स्वामित्व वाले अथवा उसके द्वारा परिचालित जलयानों, वायुयानों अथवा आधानों के अंतरण में, पैरा 1 में वर्णित किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त किए गए लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 9

सहबद्ध उद्यम

1. जहां :

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी के मित्तिले में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी के मिलाने में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं; और दोनों ही व्यवस्थाओं में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा

लगाई जाती हों, जो ऐसी शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्योगों के बीच रखी जाती हों तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की वशा में दोनों उद्योगों में से किसी एक उद्योग को प्राप्त हुआ होता परन्तु उन शर्तों के कारण वह इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, उस उद्योग के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और तदनुसार, कर लगाया जा सकेगा।

2. जहाँ पर एक संविदाकारी राज्य, उस संविदाकारी राज्य के किसी उद्योग के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है—जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्योग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार समाहित किए गए लाभ वे लाभ हैं जो प्रथमो-ल्लिखित राज्य के उन उद्योगों को उस स्थिति में प्राप्त हो गए होते यदि दोनों उद्योगों के बीच बनाई गई शर्तें इस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्योगों के बीच बनाई गई होतीं तो वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस तरह से सहमति प्राप्त लाभों पर, उन पर प्रभारित कर की मात्रा के अनुसार समचित्त समायोजन करेगा। इस तरह का समायोजन करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान रखा जाएगा तथा यदि आवश्यक होगा तो संविदाकारी राज्यों के सधम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी उस राज्य के कानूनों के अनुसार वहाँ की निवासी है लेकिन यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार से प्रभारित कर की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :—

(क) लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत यदि हितभोगी स्वामी कोई ऐसी कम्पनी है जिसके पास लाभांश अदा न करने वाली कम्पनी के वोटिंग स्टॉक के न्यूनतम 10 प्रतिशत शेयर हैं;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 25% संयुक्त राज्य अमरीका की किसी संस्था द्वारा, जो कि एक नियंत्रित निवेश कंपनी है अदा किए गए लाभांशों के मामले में उप-पैरा (ख) और न कि उप-पैरा (क) लागू होगा। संयुक्त राज्य अमरीका की कोई संस्था जो कि एक वास्तविक सम्पदा निवेश न्यास है, द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर उप-पैरा (क) लागू नहीं होगा और उप-पैरा (ख) केवल तभी लागू होगा यदि हितभोगी रूप में लाभांश किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए हों जो वास्तविक सम्पदा

निवेश न्यास में 10 प्रतिशत से कम हित रखता हो। इस पैराग्राफ से उस लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “लाभांश” शब्द का अभिप्राय—शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय है, जो ऋण दावे नहीं हों, जो लाभ से शामिल हों, अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसमें वितरण करने वाली कंपनी निवासी है और उन प्रबंधों से प्राप्त आय जिनमें वे ऋण-वेन दारियां भी शामिल हैं जिन्हें उस सीमा तक लाभों में हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त हो जिस कि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत निर्धारित किया गया हो जिसमें आय उद्भूत हुई हो।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी, जो किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है, अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ सम्पन्न करता है और लाभांश ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के कारण प्राप्त होते हों। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 (कारो-वार संबंधी लाभ) अथवा अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ) के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य के लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसे मामले में उस कम्पनी द्वारा अदा किये गये लाभांशों पर जहाँ तक ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये हों अथवा जहाँ तक कि ऐसी संपत्ति के बारे में लाभांशों की अदावगी की गई हो, जो उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में न तो कोई कर लगाया जायेगा और न ही कम्पनी को अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जायेगा, भले ही अदा किये गये लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो हों।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. किसी संविदाकारी राज्य से उत्पन्न होने वाले नगरीय दूसरे संविदाकारी राज्य को किसी निवासी को अदा किये जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा, जिम राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रधारित कर की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :

(क) ब्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि ब्याज उस बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर अदा किया गया हो जो कि वास्तव में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो या ऐसी ही विनियम संस्था (दीमा कम्पनी सहित) द्वारा अदा किया गया हो; और

(ख) सभी अन्य मामलों में ब्याज की सकल राशि का 15 प्रतिशत ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी एक संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित संदर्भ में उद्भूत होने वाला ब्याज प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगा:

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा संयुक्त राज्य के फेडरल रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, और दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त और उनके हितभोगी स्वामित्व वाला ब्याज जिसके बारे में अनुच्छेद 27 (परस्पर सहमति प्रविष्टि) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी सहमत हों ।

(ख) निम्नलिखित द्वारा दिये गये अथवा अनुमोदित किये गये ऋणों अथवा कर्जों के संबंध में :

(i) संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक द्वारा जब भारत प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य हो ;

(ii) भारत के निर्यात-आयात बैंक द्वारा जब संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथमोल्लिखित राज्य हो ।

(ग) उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक और उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त और हितभोगी रूप से धारित, जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो, बशर्ते कि उस सौदे का, जिससे कि यह ऋण-दावा उद्भूत हुआ हो प्रथमोल्लिखित राज्य का सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदन कर दिया गया हो ।

4. इस अभिसमय में यथा प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों या नहीं हों, और चाहे ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार रखते हों या नहीं रखते हों, और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम अथवा पुरस्कार भी शामिल हैं । देर से की गई अदायगी के लिये लाने वाले जुमनि को इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिये ब्याज नहीं समझा जायेगा तथापि, "ब्याज" पद में अनुच्छेद 10 (लाभान) में वर्णित आय शामिल नहीं होता ।

5. पैराग्राफ 2 और 3 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान में स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और ब्याज इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान में संबंधित हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 (व्यावसायिक लाभ) अथवा 15 (स्वतन्त्र व्यक्तित्व सेवाएं) के उपबन्ध यथास्थिति लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उस स्थिति में उद्भूत हुआ समझा जायेगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किस संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान है और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जायेगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिये उस ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिये इस प्रकार के संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभोग स्वामी के बीच सहमति हो गई होती वहां इस अनुच्छेदी के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित राशि पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जायेगा ।

अनुच्छेद — 12

रायल्टियों और शामिल सेवाओं के लिये फीस

1. एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को श्रदा की जाने वाली रायल्टियों तथा शामिल की गई सेवाओं के लिये फीस के भुगतान पर दूसरे सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों तथा शामिल की गई सेवाओं के लिये फीस पर उस सविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत होती हैं तथा उसी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा; किन्तु यदि रायल्टियों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिये फीस का हितभोगी स्वामी दूसरे सविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाये गये कर की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:

(क) पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित रायल्टियों और इस अनुच्छेद में परिभाषित शामिल सेवाओं (इस पैरे के उप-पैराग्राफ में वर्णित सेवाओं से भिन्न) के लिए फीस के मामले में:

(i) पहले पांच कराधेय वर्षों के दौरान जिनमें यह अभिसमय प्रभावी रहेगा:

(क) जहां पर रायल्टियां अथवा फीस श्रदा करने वाला उस सविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनीतिक उप प्रभाग अथवा कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो। वहां पर इस अनुच्छेद में यथापरिभाषित शामिल की गई सेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत; और

(ख) अन्य सभी मामलों में शामिल की गई सेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा फीस की सकल राशि का 20 प्रतिशत; और

(ii) अनवर्ती वर्षों के दौरान शामिल की गई सेवाओं के लिए रायल्टियों और फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत; और पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) में उल्लिखित रायल्टियों और इस अनुच्छेद में यथापरिभाषित शामिल सेवाओं के लिए फीस के मामले में जो कि उस सम्पत्ति के इस्तेमाल के लिए आनुवंशिक और सहायक स्वरूप की है, जिसके लिए इस अनुच्छेद के पैरा 3(ख) के अंतर्गत राशि प्राप्त की जाती है, रायल्टियों अथवा शामिल सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 10 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियों" शब्द से अभिप्रेत है:

(क) किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कार्य जिसमें रेडियो, दूरदर्शन के प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए चलचित्र अथवा फिल्म अथवा टेप तैयार करने का कार्य अथवा फिल्म निर्माण के अन्य साधन भी शामिल हैं, कोई पेटेन्ट ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुण फार्मुला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी जिसमें किसी ऐसे अधिकार अथवा सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभ भी शामिल हैं जो कि उत्पादकता, उपयोग अथवा उसकी बिक्री के संबंध में प्राथमिक स्वरूप के होने हैं, आदि के प्रयोग अथवा, प्रयोगाधिकार, किसी कापी-राइट के प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार की श्रदायगी; और

(ख) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग, अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में किसी प्रकार से प्राप्त की गई श्रदायगियां जिनमें अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 1 (जहाजरानी और वायु परिवहन) में वर्णित किसी उद्यम द्वारा अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2(ग) अथवा 3 में वर्णित कार्यकलापों से प्राप्त की गई श्रदायगियां शामिल नहीं हैं।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस" का अर्थ है—किसी प्रकार की तकनीकी अथवा परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए (जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्यों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं शामिल हैं) प्रतिफल के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी रूप में प्राप्त की गई श्रदायगियां, यदि ऐसी सेवाएं इस प्रकार की हों;

(क) किसी अधिकारी, सम्पत्ति अथवा सूचना, जिसके प्रयोग अथवा गहनयोग के लिए प्रदान की गई आनुवंशिक और सहायक सेवाएं, जिनके लिए पैराग्राफ 3 में वर्णित श्रदायगी प्राप्त की गई है; अथवा

(ख) ऐसी सेवाएं जिनका संबंध तकनीकी ज्ञान, अनुभव, कौशल, जानकारी अथवा प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने से हो अथवा जो विकास तथा किसी तकनीकी प्लान तकनीकी डिजाइन का हस्तांतरण करने से संबंधित हों।

5. पैराग्राफ 4 के होते हुए भी "शामिल सेवाओं के लिए फीस" में श्रदा की गई निम्नलिखित राशियां शामिल नहीं होंगी:

(क) उन सेवाओं के लिए जो आनुवंशिक और सहायक स्वरूप की और साथ ही वे पैराग्राफ 3(क) में वर्णित बिक्री से भिन्न सम्पत्ति की बिक्री से अभिभोचनीय और अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हों;

(ख) उन सेवाओं के लिए जो जलयानों, वायुयानों, आवातनों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जनयानों अथवा वायुयानों के संचालन के संबंध में इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपस्करों के किराए के संबंध में आनुवंशिक और सहायक स्वरूप की हों;

(ग) शिक्षण अथवा शैक्षिक संस्थाओं द्वारा; अथवा

(घ) उन सेवाओं के लिए जो अदायगी करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हों; अथवा

(ङ) अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को अथवा अनुच्छेद 15 में यथापरिभाषित व्यावसायिक सेवाओं के लिए (स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं) किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की कोई फर्म (किसी कम्पनी के अलावा)।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस का हितभोगी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हो, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पन्न करता हो तथा रायल्टियों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस की प्रदायगी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 (व्यावसायिक लाभ) अथवा अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं) के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

7. (क) रायल्टियां तथा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस एक संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उमका कोई राजनैतिक उप-अंश, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं है, उस संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है और ऐसी रायल्टियां अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस को ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो ऐसी रायल्टियां अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस के लिए भुगतान, उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है;

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत रायल्टियां अथवा संबंधित सेवाओं के लिए फीस किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत नहीं होती और रायल्टियां, अधिकार या सम्पत्ति के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार से संबंधित हों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस एक संविदाकारी राज्य में निष्पन्न की गई सेवाओं से संबंधित हों, तो रायल्टियां और शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस को उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा।

8. जहां अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विरोध प्रकार का

संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जो कि इस प्रकार का संबंध न होने की दशा में अदा की जाती तो वहां पर इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अधिक अदा की गई रकम इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर-योग्य होगी।

अनुच्छेद—13

लाभ

इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 (जहाजरानी और वायु परिवहन) में की गई व्यवस्था के अलावा, प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने स्वदेशी कानून के उपबंधों के अन्तर्गत पजीगत लाभों पर कर लगा सकता है।

अनुच्छेद—14

स्थायी संस्थापन कर

1. कोई कम्पनी, जो कि भारत की निवासी है, उस पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत लगने वाले कर के अलावा भी संयुक्त राज्य अमेरिका में कर लगाया जा सकता है।

(क) तथापि, ऐसा कर, केवल निम्नलिखित स्थितियों में लगाया जा सकता है:

- (i) कम्पनी के व्यावसायिक लाभों के उस हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कर लगा जो कि लाभांश की समकक्ष राशि की दर्शाता हो; और
- (ii) कम्पनी के उन लाभों को, जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कर लगा, गणना करने समय काट जाने वाले ब्याज की अधिक राशि यदि कोई हो, तो वह या तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी स्थायी संस्थापन से सम्बद्ध होगी अथवा उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में इस अभिसमय के अनुच्छेद 6 (अचल सम्पत्ति) वास्तविक सम्पत्ति (से आय), अनुच्छेद 12 (रायल्टियां और शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस) के रूप में, अथवा अनुच्छेद-13 (लाभ) के अन्तर्गत उसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित स्थायी संस्थापन अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय द्वारा अथवा उससे अदा किये गये ब्याज पर कर लगेगा।

(ख) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये, व्यावसायिक लाभ का अर्थ है वे लाभ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार अथवा व्यवसाय के संचालन के साथ प्रभावी रूप से जुड़े हैं (अथवा जिन्हें प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ समझा जाना

हो) और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी स्थायी संस्थापन से संबद्ध हों अथवा उन पर इस अभिसमय के अनुच्छेद 6(अचल सम्पत्ति) वास्तविक संपत्ति) से आय), अनुच्छेद 12 (रायल्टियों और शामिल की गई सेवाओं के लिये फीस) अथवा अनुच्छेद 13(लाग) के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में कर लगाया जाना हो।

(ग) उपर्युक्त उप पैरा (क) में उल्लिखित कर निम्नलिखित से अधिक दर पर नहीं लगाया जायेगा :

(i) उप पैराग्राफ (क) (i) में वर्णित कर के लिये अनुच्छेद 10(लाभांश) के पैरा 2(क) में निर्दिष्ट दर;

(ii) उप-पैराग्राफ (क) (ii) में वर्णित कर के लिये अनुच्छेद 11(ब्याज) के पैराग्राफ 2(क) अथवा (ख) (जा भी उपयुक्त हो) में निर्दिष्ट दर।

2. कोई कम्पनी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी हो, उस पर भारत में, स्वदेशी कम्पनियों पर लागू होने वाली दर से उच्च दर पर कर लगाया जा सकता है। तथापि, कर की दर में यह अन्तर 15 प्रतिशत प्वाइंटों की विद्यमान दर से अधिक नहीं होगा।

3. किसी बैंकिंग कम्पनी के मामले में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी है, ऐसी कम्पनी के स्थायी संस्थापन द्वारा भारत में प्रधान कार्यालय को अदा किये गए ब्याज पर भारत में, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत लगने वाले ब्याज के अलावा भी कर लगेगा। कर की यह दर अनुच्छेद 11(ब्याज) के पैराग्राफ 2(क) में निर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगी।

अनुच्छेद—15

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो कि कोई व्यक्ति अथवा व्यष्टियों की फर्म है (कंपनी से भिन्न) जो कि एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के अन्य स्वतन्त्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगेगा सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि ऐसे व्यक्ति के पास अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में उसनी ही आय पर कर लगाया जा सकेगा

जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई हो; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उस व्यक्ति की ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत कराधेय वर्ष में कुल मिलाकर 90 दिन अथवा उससे अधिक हों।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी का कलाप तथा चिकित्सों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखापासों के स्वतन्त्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद—16

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 17(निदेशकों की फीस), 18(मनोरंजन कर्ता और एथलीटों द्वारा अर्जित आय), 19(सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेन्शन), 20(प्राइवेट पेंशन, वार्षिकियों, निर्वाह व्यय और बाल-सहायता), 21(विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं, द्वारा प्राप्त की जाने वाली अदायगियां) और 22 (प्राध्यापकों, शिक्षकों और शोधकर्तियों द्वारा प्राप्त की गई अदायगियां) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो जाता हो। यदि इस प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि:

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित कराधेय वर्ष में कुल मिलाकर 183दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिये उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद रहा हो;

(ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय से बहून नहीं किया गया हो, जो कि नियोजक के दूसरे संविदाकारी राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में किसी जलयान अथवा वायुयान पर सवार होकर उसके परिचालन में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद—17

निदेशकों की फीस

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कंपनी के निदेशक मण्डल के एक सदस्य की हैसियत में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस और अन्य समरूप अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद—18

मनोरंजनकर्ताओं और एथलीटों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 15 (स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं) और 16 (पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं) के उपबन्धों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के द्वारा, मनोरंजनकर्ता के रूप में जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार, अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी एथलीट के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार सम्पन्न किये गये अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, सिवाय उस स्थिति के जहां पर ऐसे मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट द्वारा ऐसे कार्यकलापों से अर्जित संबंधित कराधेय वर्ष की निवल आय (उसकी यात्रा और कार्य-निष्पादन के संबंध में उसके द्वारा किये गये सभी खर्चों को हटाने के बाद) एक हजार पांच सौ संयुक्त राज्य अमेरिका डालरों (1,500) अथवा भारत में इसके समकक्ष रूपों से अधिक नहीं हो।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट द्वारा अपनी उसी हैसियत से किये गये कार्यकलापों से उद्भूत आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट को प्रोद्भूत न होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है जो अनुच्छेद 7 (व्यावसायिक लाभ), 15 (स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं) और 16 (पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं) के उपबन्धों के होते हुए भी उस दूसरे व्यक्ति की आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जायेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट के कार्यकलाप निष्पादित हुए हों जब तक कि मनोरंजनकर्ता या एथलीट अथवा अन्य व्यक्ति यह प्रमाणित नहीं करता है कि न तो मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट और न ही उनसे संबंधित व्यक्ति आस्थायित पारिश्रमिक बोनस फीस, लाभान्शों, भागीदारी वितरणों अथवा अन्य वितरणों की पुष्टि सहित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी भी तरह उस दूसरे व्यक्ति के लाभों में भागीदार है।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये कार्यकलापों से अर्जित आय पर जिसका इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है, दूसरे राज्य में कर नहीं लगेगा यदि दूसरे राज्य में मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट की यात्रा का व्यय पूर्ण अथवा पर्याप्त रूप से प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण की सार्वजनिक निधियों द्वारा वहन किया गया हो।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, परस्पर सहमति से, आर्थिक अथवा मुद्रा संबंधी घटना चक्रों को दर्शाने के लिये पैरा 1 में उल्लिखित डालरों की राशि में वृद्धि कर सकते हैं।

अनुच्छेद—19

सरकारी सेवा के लिये पारिश्रमिक और पेंशन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके किसी उपप्रभाग अथवा किसी प्राधिकरण के लिये प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल उस स्थिति में लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(ii) सेवाएं संपन्न करने के प्रयोजनार्थ केवल उस राज्य का निवासी नहीं बना।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके किसी उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिये सम्पन्न की गई सेवाओं के संबंध में सृजित निधियों के द्वारा अदा की गई अथवा ऐसी निधियों में से, अदा की गई किसी पेंशन पर उस राज्य में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर उस स्थिति में लगेगा, यदि व्यक्ति उस राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक है। अनुच्छेद 16 (पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं) 17 (निदेशकों की फीस), 18 (मनोरंजनकर्ताओं और एथलीटों द्वारा अर्जित आय) और 20 (प्राइवेट पेंशन, वार्षिकियां, जीवन-निर्वाह और बाल-सहायता) के उपबन्ध एक संविदाकारी राज्य, उसके राजनीतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी कारोबार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा किये गये पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद—20

प्राइवेट पेंशन, वार्षिकता, जीवन-निर्वाह व्यय और बाल-सहायता

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के अंदर उपलब्ध स्रोतों से अनुच्छेद 19 (सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन) में उल्लिखित पेंशन से भिन्न कोई अन्य पेंशन अथवा वार्षिकी प्राप्त हुई हो, तो उस पर केवल प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के हाते हुए भी, और अनुच्छेद 19 (सरकारी सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भी एक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी नागरिक को प्रदान किये गये सामाजिक सुरक्षा लाभों और अन्य पब्लिक पेंशनों पर केवल प्रथमोलिखित राज्य में ही कर लगेगा।

3. "पेंशन" शब्द का अर्थ है पिछली सेवाओं का ध्यान में रखते हुए अथवा सेवाओं के कार्य-निष्पादन के दौरान चाटग्रस्त होने के लिये प्रतिपूर्ति के रूप में की गई कोई आवधिक अदायगी।

4. "वार्षिकी" शब्द का अर्थ उस नियम राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य (परन्तु प्रदान की गई सेवाओं के लिये नहीं) में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिये अदायगिप्रा करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित अवधि के दौरान निवृत्त समय पर देय हों।

5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी का अदा किये गये जीवन-निर्वाह व्यय पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा। इस पैराग्राफ में प्रयुक्त "जीवन-निर्वाह व्यय" शब्द का अर्थ, किसी ऐसे संबंध विच्छेद करारनामे अथवा तलाक की डिग्री, पृथक् रहने के निर्वाह व्यय अथवा अनिवार्य सहायता के किसी लिखित आदेश के अनुसरण में की जान वाली आवधिक अदायगियों से है जिन पर उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत कर लगेगा जिसका कि वह निवासी है।

6. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को संबंध विच्छेद करारनामे, तलाक की डिग्री, अलग रहने के लिये निर्वाह व्यय, अनिवार्य सहायता के किसी लिखित आदेश के अनुसरण में किसी भावार्थिक बच्चे के भरण-पोषण के लिये की जाने वाली आवधिक अदायगियों पर केवल प्रथमोलिखित राज्य में ही कर लगेगा।

अनुच्छेद—21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु, जो किसी अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मुख्यतया अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में रह रहा है, उसे अपनी जीविका, शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य के बाहर उद्भूत होने वाली अदायगियों पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत न आने वाले अनुदानों, छात्रवृत्तियों और नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिकों के संबंध में, किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जिसका वर्णन पैराग्राफ 1 में किया गया है, इसके अतिरिक्त, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के दौरान करों के संबंध में वैसी ही छूटें, राहतें अथवा कटौतियां प्राप्त करने का हक होगा जैसा कि उस राज्य के निवासियों का प्राप्त हो जिसकी कि वह यात्रा कर रहा है।

3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि तक के लिये ही लागू रहेंगे जो शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिये उचित रूप से अथवा साधारणतया अपेक्षित हों।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा यदि वह उस उक्त संविदाकारी राज्य का उस कराधेय वर्ष में, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करता है, अथवा उसका तत्काल पूर्ववर्ती कराधेय वर्ष में निवासी रहा हो।

अनुच्छेद—22

प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा शोध-छात्रों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. कोई व्यक्ति, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अध्यापन अथवा अनुसंधान के प्रयोजनार्थ दो वर्ष से अतिधिक अवधि के लिये उस राज्य की यात्रा करता है तथा जो इस तरह की यात्रा के तत्काल पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी था, तो उसे इस प्रकार के अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य के लिये प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उस तारीख से दो वर्ष से अतिधिक अवधि के लिये जिसको वह ऐसे प्रयोजन के लिये उस राज्य की प्रथम यात्रा करता है प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा कर-छूट प्रदान की जायेगी।

2. यह अनुच्छेद केवल अनुसंधान कार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा यदि ऐसा अनुसंधान कार्य किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक हित में किया जाता है और मूलतः वह कार्य किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 23

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जहाँ कहीं वे उत्पन्न होती हैं, जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया हो, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अनुच्छेद 6 (अचल सम्पत्ति से आय) (वास्तविक सम्पत्ति) के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्त करने वाला हितभोगी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस संविदाकारी राज्य में व्यापार चलाता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ निष्पन्न करता है और यह आय ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) अथवा अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ) जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जिस पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

अनुच्छेद—24

लाभों की परिसीमा

1. कोई व्यक्ति (किसी व्यक्ति से भिन्न), जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य से आय प्राप्त करता है तो उसे उस अभिसमय के अन्तर्गत दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधान से छूट पाने का हक तभी प्राप्त होगा यदि :

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में 50 प्रतिशत से अधिक हितभोगी लाभ (अथवा किसी कंपनी के संबंध में कंपनी के शेयरों की प्रत्येक प्रकार की शेणी के 50 प्रतिशत से अधिक शेयर) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य के किसी निवासी व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों; किसी एक संविदाकारी

राज्य या उसके राजनैतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरणों या अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित हों, जिन पर दोनों संविदाकारी राज्यों में उनकी विषय-भर की आय पर कर लगाया जाएगा; या वे संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिक हों;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की आय से एक बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों की देनदारियों (व्याज या रायल्टियों के लिए देनदारियों सहित) को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता हो, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य के निवासी न हों या जो किसी एक संविदाकारी राज्य या उसके राजनैतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरणों के निवासी न हों या जो संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिक न हों।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त होने वाली आय प्रथमोल्लिखित राज्य में व्यापार या कारोबार के संबंध में प्राप्त हुई हो अथवा किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार अथवा कारोबार के सक्रिय संचालन के प्रासंगिक रूप में हुई हो (कारबार का संचालन निवेश करने या निवेश का प्रबंध करने के कारोबार से भिन्न होना चाहिए, जब तक कि ये कार्यकलाप बैंकिंग या बीमा संबंधी कार्यकलापों की श्रृंखला में हों जिन्हें किसी बैंक या किसी बीमा कंपनी द्वारा चलाया जाता है)।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी हो जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है जिसके प्रमुख शेणी के शेयरों का मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में पर्याप्त और नियमित रूप से व्यापार होता हो। पूर्ववर्ती वाक्य के प्रयोजनों के लिए "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" पद का अर्थ है :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में नेशनल एसोसिएशन आफ मिक्यूरिटीज डीपनरेंस इंका द्वारा धारित नसडाक पद्धति तथा 1934 के प्रतिभूति अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नेशनल मिक्यूरिटीज एक्सचेंज के रूप में कोई मिक्यूरिटीज तथा एक्सचेंज कमीशन में पंजीकृत कोई शेयर बाजार;

(ख) भारत के संबंध में, यदि कोई ऐसा शेयर बाजार जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त हो; और

(ग) कोई अन्य शेयर बाजार जिसे पर संविदाकारी राज्यों के सभ्य प्राधिकारी सहमत हों।

4. कोई व्यक्ति जो इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैरों के उपबंधों के कारण इस अभिसमय के लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है तो भी उसे इस अभिसमय के लाभ दिए जा सकते हैं वशर्त कि उस राज्य के मक्षम प्राधिकारी, जिसमें उक्त आय प्रोद्भूत होती हो, ऐसा विनिर्दिष्ट करे।

अनुच्छेद—25

दोहरे कराधान से राहत

1. संयुक्त राज्य अमरीका के कानून के उपबंधों के अनुसार और उसकी परिसीमाओं के अध्याधीन रहते हुए (जैसा इस सामान्य सिद्धांत को परिवर्तन किए बिना समय-समय पर संशोधित किया गया हो), संयुक्त राज्य अमरीका अपने किसी निवासी अथवा नागरिक को निम्नलिखित प्रकार की आय पर संयुक्त राज्य अमरीका के कर के मुकाबले क्रेडिट के रूप में अनुमति देगा :

(क) ऐसे नागरिक अथवा निवासी द्वारा अथवा उनकी ओर से भारत को संवत् आयकर, तथा

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका को किसी ऐसी कंपनी के मामले में जो कि भारत के निवासी किसी कंपनी के कम से कम 10 प्रतिशत पोटिंग स्टॉक का स्वामी है और जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका की कंपनी भागीश प्राप्त करती हो, तो वितरण करने वाली कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से उन अनुलाभों के संबंध में जिनमें से भागीश अदा किए गए हों, भारत में अदा किया गया आयकर।

इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, अनुच्छेद 3 (इसके अन्तर्गत आने वाले कर) के पैराग्राफ 1ख और 2 में उल्लिखित करों को आयकर माना जाएगा।

2. (क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में भारत उस निवासी को उस आय पर कर से कटौती की अनुमति उतनी रकम के बराबर देगा, जितनी रकम की अदायगी संयुक्त राज्य अमरीका में कर के लिए की गई हो, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो अथवा कटौती के द्वारा दिया गया हो। किन्तु ऐसी कटौती की राशि आयकर (कटौती दिए जाने से पूर्व गणनागणित) के उतने भाग से अधिक नहीं होगी, जो यथास्थिति उस आय के कारण उत्पन्न हुई हो, जिस पर संयुक्त राज्य अमरीका में कर लगाया जा सकता है;

(ख) इसके अतिरिक्त, जहां ऐसा निवासी एक कंपनी है, जिसके माध्यम से भारत में अतिकर देय बनता हो, वहां संयुक्त राज्य अमरीका में अदा किए गए आयकर के संबंध में कटौती की

अनुमति प्रथमतया उस कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर से देगा और शेष रकम पर, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय अतिकर की अनुमति देगा।

3. इस अनुच्छेद के अधीन दोहरे कराधान से राहत देने के प्रयोजनों के लिए उद्भूत आय निम्नानुसार समझी जाएगी :

(क) किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है (अनुच्छेद-1) सामान्य क्षेत्र (के पैराग्राफ 3 के अनुसार केवल नागरिकता के कारण से भिन्न कारण), उस दूसरे राज्य में उद्भूत समझी जाएगी;

(ख) किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय जिस पर इस अभिसमय के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है प्रथमोल्लिखित राज्य में उद्भूत हुई समझी जाएगी।

पूर्ववर्ती वाक्य के होते हुए भी इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए आय के स्रोत का निर्धारण संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में ऐसे स्रोत नियमों के अध्याधीन किया जाएगा जैसा कि विदेश कर क्रेडिट को सीमित करने के प्रयोजन के लिए लागू होगा। पूर्ववर्ती पैरा, अनुच्छेद 12 (शामिल की गई सेवाओं के लिए रायल्टियां तथा फीमें) में विचार की गई आय के संबंध में लागू नहीं होगा। इस पैराग्राफ के नियम, अनुच्छेद 2 (अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर) के पैराग्राफ 1(ख) और 2 उल्लिखित करों में भिन्न विदेशी करों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के कर के प्रति क्रेडिट निर्धारण करने में लागू नहीं हों।

अनुच्छेद 26

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा भारपूर्ण हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर समान परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है। यह उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) के पैराग्राफ 3 के उपबंध जहां लागू होते हैं, उनको छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे

संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में समान कार्य-कलापों में लगे हुए उद्यमों पर लगाया जाता है। इस उपबंध में निहित किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी हैं, नागरिक हैसियत अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूटें, राहतें और कटौतियाँ प्रदान करने की बाध्य होगा, जो वह अपने स्वयं के निवासियों को प्रदान करता है।

3. अनुच्छेद 9 (सहबद्ध उद्यम) के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 (व्याज) के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 (शामिल की गई सेवाओं के लिए रायल्टियाँ और फीसों) के पैराग्राफ 8 के उपबंध जहां लागू होते हैं उनको छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को प्रथमोलिखित निवासी कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अदा किए गए व्याज, रायल्टियों तथा अन्य भुगतानों को उन समान परिस्थितियों के तहत कटौती योग्य माना जाएगा, यदि उनकी अदायगी प्रथमोलिखित राज्य के किसी निवासी को की गई हो।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोलिखित राज्य के अन्य इसी तरह के उद्यमों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह दोनों संविदाकारी राज्यों को अनुच्छेद 14 (स्थायी संस्थापन कर) में वर्णित करें अथवा अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित परिसीमाओं को लागू करने से रोकता है।

अनुच्छेद-27

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है अथवा लगाया जाएगा, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन संविदाकारी राज्यों के घरेलू नियमों द्वारा उपबंधित उपचारी उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रख सकता है जिसका वह नियामी है अथवा राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्य की सूचना प्राप्ति की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3376 GI/90 3

जिसके कारण इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कर नहीं लगा है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की धृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। प्राप्त हुए किसी भी समझौते को किसी तरह की समय-सीमा अथवा अन्य कार्यविधि संबंधी परिसीमाओं पर ध्यान न देते हुए संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।

3. इस अभिसमय को व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाईयाँ अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी व्यवस्था इस अभिसमय में नहीं की गई है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस पूर्ववर्ती पैराग्राफों में व्यक्त अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे के साथ प्रत्यक्षतः पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से इस अनुच्छेद में की गई पारस्परिक करार संबंधी कार्यविधि को क्रियान्वित करने के लिए समुचित द्विपक्षीय कार्यविधियों, शर्तों, पद्धतियों तथा रीतियों को तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित द्विपक्षीय कार्यों और पारस्परिक करार संबंधी कार्यविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए समुचित एकपक्षीय कार्यविधियों, शर्तों, पद्धतियों तथा तकनीकों के बारे में विचार कर सकते हैं।

अनुच्छेद-28

सूचना तथा प्रशासनिक सहायता का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित, जहां तक उसके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है, विशेषतया इस अभिसमय के अथवा संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने अथवा राजस्व आवंचन को रोकने के लिए अथवा ऐसे करों की जालसाजी को रोकने के लिए आवश्यक है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 (सामान्य क्षेत्र) द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगा, किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त सूचना को उसी भांति से जिस भांति से उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत सूचना प्राप्त होती है, गोपनीय समझा जाएगा। तथापि, यदि सूचना को प्रेषण करने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो इसे उस अभिसमय में समाविष्ट करों के निर्धारण, उनकी वसूली अथवा उनको लागू करने, उनका प्रवर्तन करने अथवा

उनके बारे में अभियोजन संबंधी कार्यवाई करने में तथा उनसे संबंधित अग्रीलों का निर्धारण करने में लगे हुए व्यक्तियों तथा प्राधिकरणों (जिनमें न्यायालय तथा प्रशासनिक निहाय भी शामिल हैं) को ही प्रकट किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण ऐसे प्रयोजनों के लिए ही सूचना का हस्तान्तरण कर सकेंगे लेकिन वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से सूचना के ऐसे आदान-प्रदान के संबंध में उन मामलों की समुचित शर्तों, पद्धतियों तथा तकनीकों को तैयार करेंगे जिसमें जहां उचित होगा, कर परिवार के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना भी शामिल होगा।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो किसी नेमी आधार पर होगा या मामलों विशेष के संदर्भ में किसी अनुरोध पर अथवा होगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उस सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर समय-समय पर सहमत होंगे जिसे किसी नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जिसमें कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डाला जाए :

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना देना कि एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति से प्राप्त नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना देना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यवसाय संबंधी गुप्त-भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा ऐसी सूचना, प्रकट होती है, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति (ओडरी पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य उसी रीति में और रूप में उस सूचना को प्राप्त करेगा जिसके संबंध में अनुरोध किया गया है जैसा कि मानो प्रथम-उल्लिखित राज्य के कर उस दूसरे राज्य के कर थे और उस दूसरे राज्य द्वारा ही लगाए जा रहे थे। यदि किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिष्ट रूप से अनुरोध किया जाता है, तो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत साक्ष्यों और बिना सम्पादित किए गए मूल दस्तावेजों (जिनमें पुस्तकें, कागज-पत्र, विवरण-पत्र, अभिलेख, लेखे तथा हस्तलेख भी शामिल हैं) की प्रमाणित प्रतियों को जमा करवाकर सूचना उपलब्ध करायेंगा। यहां तक कि उनके अपने करों के संबंध में ऐसे निक्षेपण तथा दस्तावेज भी इसी प्रकार उस

दूसरे राज्य के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अंतर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अनुच्छेद 2 (अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर) के उपबंधों के होते हुए भी, यह अभिसमय निम्नलिखित पर लागू होगा :—

- (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका कोड के शीर्षक 26 के अंतर्गत लगाए गए सभी करों; और
- (ख) भारत के संबंध में, आयकर, धनकर और दान-कर।

अनुच्छेद-29

राजनयिक एजेन्ट्स तथा कौंसली अधिकारी

अन्तरराष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावधानों के अंतर्गत इस अभिसमय के कारण राजनयिक अधिकारियों अथवा कौंसली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-30

प्रवर्तन

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को राजनयिक माध्यमों द्वारा इस अभिसमय को लागू करने के लिए उनकी अपनी कानूनी कार्यविधियों के पूरा होने पर लिखित रूप में अधिसूचित करेगा।

2. यह अभिसमय ऐसी अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और इसके उपबंधों का निम्नानुसार प्रभाव होगा :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में,

(1) स्रोत पर लगाए जाने वाले करों को रोकने के संबंध में, जिस तारीख को यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद संवत्स रकमों अथवा जमा राशियों के लिए;

(2) अन्य करों के संबंध में, जिस तारीख को यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले कराधेय अवधियों के लिए; तथा

(ख) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कराधेय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

अनुच्छेद-31

समाप्ति

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य

इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष के जून मास के 30वें दिन को अथवा उससे पहले राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में :

- (i) स्रोत पर लगाए जाने वाले करों को रोकने के संबंध में जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् संवत् रक्तों अथवा जमा राशियों के संबंध में; और
- (ii) अन्य करों के संबंध में, जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है इसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाली कराधेय अवधियों के लिए; और

(ख) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी कराधेय वर्ष में उद्भूत होने वाले आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

सन् एक हजार नौ सौ नवासी के नौवें माह के बारहवें दिन को नई दिल्ली में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके दोनों पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। दोनों पाठों के बीच किसी प्रकार की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की	संयुक्त राज्य अमेरिका की
सरकार की ओर से	सरकार की ओर से
ह०	ह०
एन. के. सेनगुप्ता	जॉन प्रार. हब्बर्ड,
सचिव, भारत सरकार	राजदूत

प्रोतीकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अयंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आज हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हो गए हैं जो कि इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे।

I. अनुच्छेद 5

इस अनुच्छेद के अनुसार यह सहमति हुई है कि जहां किसी संविदाकारी राज्य के किंगी उद्यम का अनुच्छेद 5

(स्थायी संस्थापन) के पैराग्राफ 2(ड), 2(ट) अथवा 2 (ठ) के उपबन्धों के अनुसार किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है तथा उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित समयावधि का विस्तार दो कराधेय वर्षों तक होना है तो उस स्थिति में किसी वर्ष में, यदि कोई हो, स्थायी संस्थापन का अस्तित्व में होता नहीं माना जाएगा जब किसी कराधेय वर्ष में उस स्थायी संस्थापन का हस्तमाल, इसके स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप, जैसी भी स्थिति हो, कुल मिलाकर तीस दिनों से कम की अवधि अथवा अवधियों के लिए जारी रहता हो। किसी स्थायी संस्थापन का अस्तित्व दूसरे कराधेय वर्ष में होना माना जाएगा तथा इस उद्यम पर अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) के उपबन्धों के अध्वधीन दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा लेकिन यह उतनी ही आय पर लगेगा जितनी उस अन्य कराधेय वर्ष में उद्भूत हुई हो।

II. अनुच्छेद 7

इस अनुच्छेद के अनुसार जहां किसी संविदाकारी राज्य, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है, के कानून अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) के पैरा 3 के उपबन्धों के अध्वधीन कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्चों की राशि पर, जिसकी ऐसे स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है, प्रतिबंध लगाते हों, तो उस स्थिति में यह सहमति हुई है कि लाभों का ऐसा निर्धारण करते समय ऐसे कार्यकारी तथा प्रशासनिक खर्चों के संबंध में कटौती की राशि किसी भी हालत में उस राशि से कम नहीं होगी जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख को भारतीय आयकर अधिनियम के अध्वधीन अनुमध्य हो।

III. अनुच्छेद 7, 10, 11, 12, 15 और 23

इन अनुच्छेदों के अनुसार यह सहमति हुई है कि अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) के पैरा 1 और 2, अनुच्छेद 10 (लाभांश) के पैरा 4, अनुच्छेद 11 (व्याज) के पैरा 5, अनुच्छेद 12 (रायल्टियां और मौखिक सेवाओं के लिये फीस) के पैरा 6, अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) के पैरा 1 तथा अनुच्छेद 23 (अन्य आय) के पैरा 2 के कार्यान्वयन के लिए, किसी स्थायी संस्थापन अथवा स्थिर आस्थान के अस्तित्व में रहने के दौरान उद्भूत हुई किसी आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें ऐसा स्थायी संस्थापन अथवा फिर आस्थान स्थित है चाहे ऐसी अदायगियों को तब उस अवधि तक आस्थगित रखा गया हो जब तक ऐसा स्थायी संस्थापन अथवा स्थिर आस्थान बन्द नहीं हो जाता है।

IV. अनुच्छेद 12

इस अनुच्छेद के अनुसार यह सहमति हो गई है कि अनुच्छेद 12 (अन्तर्विष्ट सेवाओं के लिए रायल्टियां तथा फीस) के पैरा 4 में यथा परिभाषित अन्तर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य

अमेरिका के कानून के अनुसार सकल आय के आधार पर कर लगेगा, जब ऐसी आय किसी कंपनी द्वारा अर्जित की गई हो तो इस पर वे कर लगेंगे जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14 (स्थायी संस्थापन कर) के पैरा 1 में किया गया है। तथापि, इस प्रकार की फीसों पर लगाए गए इन करों की कुल राशि अनुच्छेद 12 के पैरा 2 के उप पैरा (क) अथवा (ख), जो भी लागू होते हों, में विनिर्दिष्ट यथाप्रयुक्त कर की दर से सकल फीस का गुणन करने पर आकलित राशि में अधिक नहीं होगी।

V. अनुच्छेद 14

इस अनुच्छेद के अनुसार यह सहमति हुई है कि अनुच्छेद 14 (स्थायी संस्थापन कर) के पैरापा 1 में जिन ऐसे लाभों का, जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुच्छेद 6 (अच्छ संपत्ति) वास्तविक संपत्ति (से आय), अनुच्छेद 12 (अनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए रायटियां तथा फीस) के अंतर्गत उस अनुच्छेद में यथा परिभाषित अथवा इस अभिसमय के अनुच्छेद 13 (अनुलाभ) के अनुसार फीस के रूप में कर लगाया जाता है, उल्लेख है उसका आणव्य केवल उन मामलों से है जिनमें प्रस्तुत लाभों पर निवल आय के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कर लगाया जाता है (अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार अथवा कारोबार के संबंध में जो प्रभावी रूप से संबंधित है अथवा जिन्हें प्रभावी रूप से संबंधित माना गया है)। ऐसी किसी भी आय पर, जिस पर उक्त अनुच्छेदों के अधधीन सकल आय के आधार पर कर लगाया जाता है, अनुच्छेद 14 के अधधीन कर नहीं लगाया जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, संबंधित सरकारों के यथा-प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

सन एक हजार नाँ सी नवासी के तीबें माह के बारहवें दिन को नई दिल्ली में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निष्पन्न किया गया जिसके दोनों पाठ समान रूप से अधि-प्रमाणित हैं। दोनों पाठों में भिन्नता के मामलों में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार	संयुक्त राज्य अमेरिका की
की ओर से	सरकार की ओर से
ह०	ह०
एन. के. सेमगुप्ता	जॉन आर. हव्वर्ड
सचिव, भारत सरकार	राजदूत
	संयुक्त राज्य अमेरिका का
	दूतावास, नई दिल्ली
	दिनांक 12 सितम्बर, 1989

महामहिम,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के

ीव निष्पन्न किए गए अभिसमय, जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं (जिसे एतदपश्चात् "अभिसमय" कहा जाएगा), का हवाला देने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की ओर से दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई निम्नलिखित पारस्परिक सहमतियों की पुष्टि करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समय इस अभिसमय के अनुच्छेद 25 (बोहरे कराधान में राहत) में कर छूट लाभ (टेक्स स्पेयरिंग क्रेडिट) की सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन टेक्स स्पेयरिंग क्रेडिट के उपबन्ध का समावेश करने के लिए इस अभिसमय का उस स्थिति में तुरन्त मशौघत कर दिया जाएगा यदि संयुक्त राज्य अमेरिका टेक्स स्पेयरिंग क्रेडिट के उपबन्ध से संबंधित अपने कानूनों में एतद् पश्चात् संशोधन करता है अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका टेक्स स्पेयरिंग क्रेडिट के उपबन्धों के संबंध में किसी दूसरे देश के साथ कोई करार करता है।

दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 (स्थायी संस्थापन) के पैरा 4 (ग) के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को किसी उद्यम के लिए पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः रूप से किसी संविदाकारी राज्य में आदतन आर्डर प्राप्त करने वाला तभी माना जाएगा यदि :

- (1) ऐसा व्यक्ति किसी उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य वस्तुओं के लिए अकसर आर्डर स्वीकार करता हो।
- (2) ऐसे व्यक्तियों के किसी संविदाकारी राज्य में बिक्री से संबंधित कार्यकलाप पर्याप्ततः उद्यम के कार्य-कलापों के लिए ही किए गए हों;
3. ऐसा व्यक्ति आदतन माल अथवा पण्य वस्तुओं की खरीद की पेशकश करने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो जो कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया गया आदेश उस उद्यम द्वारा माल अथवा पण्य वस्तुओं की सप्लाई के लिए किए गए करार का एक भाग हो तथा ऐसा उक्त आर्डर में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा विनियमों के अधधीन किया गया हो।
- (4) उद्यम द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की गई हो जिसके आधार पर क्रेता को युक्तियुक्त विश्वास करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उद्यम के लिए आबद्ध करने का प्राधिकार प्राप्त है।

महामहिम मुझे आपसे यह अनुरोध करने का गौरव प्राप्त हुआ है कि आप अपने महामहिम की सरकार की उपर्युक्त सहमतियों की पुष्टि करें।

मैं इस अवसर पर आपको अपनी परम आदर भावना का पुनः आश्वासन देता हूँ।

जॉन आर. ह्यूबर्ड

महामहिम
डा. नीतीश सेनगुप्ता
सचिव (राजस्व)
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
नई दिल्ली,

दिनांक 12 सितम्बर, 89

महामहिम

मुझे आपके महामहिम की आज की टिप्पणी की प्राप्ति की सूचना देने का गौरव प्राप्त हुआ है जो कि निम्नानुसार है:—

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच निष्पन्न किए गए अभिसमय, जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं (जिस एतद्वशात् "अभिसमय" कहा जाएगा), का हवाला देने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की ओर से दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई निम्नलिखित पारस्परिक सहमतियों की पुष्टि करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है :

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समय इस अभिसमय के अनुच्छेद 25 (दोहरे कराधान से राहत) में कर छूट लाभ (टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट) की सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट के उपबंध का समावेश करने के लिए इस अभिसमय को उस स्थिति में तुरन्त संशोधित कर दिया जाएगा यदि संयुक्त राज्य अमेरिका टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट के उपबंध में संबंधित अपने कानूनों में एतद्वशात् संशोधन करता है अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट के उपबंधों के संबंध में किसी दूसरे देश के साथ कोई करार करता है।

दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 (स्थायी संस्थापन) के पैरा 4 (ग) के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को किसी उद्यम के लिए पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः रूप से किसी सविदाकारी राज्य में आश्रय प्राप्त करने वाला तभी माना जाएगा यदि :

1. ऐसा व्यक्ति किसी उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य वस्तुओं के लिए अक्सर आर्डर स्वीकार करता हो;

2. ऐसे व्यक्तियों के किसी सविदाकारी राज्य में बिक्री से संबंधित कार्यकलाप पर्याप्ततः उद्यम के कार्यकलापों के लिए ही किए गए हों;

3. ऐसा व्यक्ति आदतन माल अथवा पण्य वस्तुओं की खरीद की पेशकश करने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो जो कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया गया आदेश उस उद्यम द्वारा माल अथवा पण्य वस्तुओं की सप्लाई के लिए किए गए करार का एक भाग हो तथा ऐसा उक्त आर्डर में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा विनियमों के अधीन किया गया हो ;

4. उद्यम द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की गई हो जिसके आधार पर क्रेता को मुक्तियुक्त विश्वास करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उद्यम के लिए आवश्यक करने का प्राधिकार प्राप्त है।

मुझे भारत गणराज्य की सरकार की ओर से आपके महामहिम की टिप्पणी में निहित सहमतियों की पुष्टि करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

मैं इस अवसर पर आपको अपनी परम आदर भावना का पुनः आश्वासन देता हूँ।

नीतीश सेनगुप्ता

महामहिम
डा. जॉन आर. ह्यूबर्ड
राजदूत
संयुक्त राज्य अमेरिका
नई दिल्ली

संयुक्त राज्य अमेरिका
का दूतावास, नई दिल्ली
दिनांक 12 सितम्बर, 1989

महामहिम

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकथाम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत गणराज्य के बीच आज हस्ताक्षर किये गये इस अभिसमय का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मुझे निम्नलिखित तथ्य आपको सूचित करने का गौरव प्राप्त हुआ है :

बातचीत के दौर के दौरान, जिसके परिणामस्वरूप आज हस्ताक्षरित यह अभिसमय निष्पन्न हुआ है, वार्ताकारों के बीच एक समझौता जापान के बारे में सहमति हुई है, जिसकी मंशा अन्तर्विष्ट की गई सेवाओं के क्षेत्र विस्तार से संबंधित अनुच्छेद 12 (अन्तर्विष्ट की गई सेवाओं के लिए रायवटिंग तथा फीस) के पहलुओं का अर्थनिरूपण करने के लिए हमारे दोनों देशों के कर-व्याताओं तथा कर-प्राधिकारियों, दोनों को ही मार्ग-निर्देश देना है। यह समझौता जापान अनुच्छेद 12 के इन पहलुओं के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा मेरे

देश की सरकार भी यह समझती है कि भारत की सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण भी यही है। मेरी सरकार का यह भी अभिमत है कि चूंकि हमारे दोनों देशों की सरकारों को इस अभिसमय को लागू करने और विशेष रूप से अनुच्छेद 12 को लागू करने में अनुभव प्राप्त होगा इसलिए सक्षम प्राधिकारी इस सहमति जापन तथा इस अभिसमय पर अन्य सहमतियों तथा अर्थनिरूपण के संबंध में संशोधन के बारे में विचार करेंगे तथा उन्हें प्रकाशित करेंगे।

यदि इस स्थिति से भारत गणराज्य की सरकार सहमत हो तो इस पत्र तथा इसके संदर्भ में आपके उत्तर से यह संकेत मिलेगा कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 12 से संबंधित सहमति जापन के प्रयोजनार्थ हमारे दोनों देशों की सरकारों का सम्मिलित रूप से समान दृष्टिकोण है।

मैं इस अवसर पर आपको अपनी परम आदर भावना का पुनः आश्वासन देता हूँ।

जॉन आर. हव्वर्ड

महामहिम
डा. नीतीश सेनगुप्ता
सचिव (राजस्व)
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
नई दिल्ली,

दिनांक 12 सितम्बर, 1989

महामहिम

मुझे आपके महामहिम की आज की टिप्पणी की प्राप्ति की सूचना देने का गौरव प्राप्त हुआ है जो निम्नानुसार है :-

“आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत गणराज्य के बीच आज हस्ताक्षर किये गये इस अभिसमय का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मुझे निम्नलिखित तथ्य आपको सूचित करने का गौरव प्राप्त हुआ है:

बातचीत के दौर के दौरान, जिसके परिणामस्वरूप आज हस्ताक्षरित यह अभिसमय निष्पन्न हुआ है, वार्ताकारों के बीच एक समझौता जापन के बारे में सहमति हुई है, जिसकी मंशा अन्तर्विष्ट की गई सेवाओं के क्षेत्र विस्तार से संबंधित अनुच्छेद 12 (अन्तर्विष्ट की गई सेवाओं के लिए रायल्टियां तथा फीस) के पहलुओं का अर्थनिरूपण करने के लिए हमारे दोनों देशों के करदाताओं तथा कर-प्राधिकारियों, दोनों को

ही मार्ग-निर्देश देना है। यह समझौता जापन अनुच्छेद 12 के इन पहलुओं के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा मेरे देश की सरकार भी यह समझती है कि भारत की सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण भी यही है। मेरी सरकार का यह भी अभिमत है कि चूंकि हमारे दोनों देशों की सरकारों को इस अभिसमय को लागू करने और विशेष रूप से अनुच्छेद 12 को लागू करने से अनुभव प्राप्त होगा इसलिए सक्षम प्राधिकारी इस सहमति जापन तथा इस अभिसमय पर अन्य सहमतियों तथा अर्थनिरूपण के संबंध में संशोधन के बारे में विचार करेंगे तथा उन्हें प्रकाशित करेंगे।

यदि इस स्थिति से भारत गणराज्य की सरकार सहमत हो तो इस पत्र तथा इसके संदर्भ में आपके उत्तर से यह संकेत मिलेगा कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 12 से संबंधित सहमति जापन के प्रयोजनार्थ हमारे दोनों देशों की सरकारों का सम्मिलित रूप से समान दृष्टिकोण है।”

मुझे भारत गणराज्य की सरकार की ओर से आपके महामहिम की टिप्पणी में निहित सहमतियों की पुष्टि करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

मैं इस अवसर पर आपको अपनी परम आदर भावना का पुनः आश्वासन देता हूँ।

नीतीश सेनगुप्ता

महामहिम
डा. जॉन आर. हव्वर्ड
राजदूत
संयुक्त राज्य अमेरिका
नई दिल्ली

दिनांक , 15 मई, 1989

संयुक्त राज्य अमेरिका—भारत कर संधि
अनुच्छेद 12 में अन्तर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस से
संबंधित समझौता जापन

पैरा 4 (साधारणतः)

इस जापन में अनुच्छेद 12 (अन्तर्विष्ट सेवाओं के लिए रायल्टियां तथा फीस) के पैरा 4 में यथापरिभाषित सेवाओं की श्रेणियों का कुछ विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें उन सेवाओं के उदाहरण भी दिए गए हैं जिन्हें अन्तर्विष्ट सेवाओं की परिभाषा के भीतर लाये जाने की मंशा है और जिन्हें शामिल न किए जाने की मंशा है चाहे उनसे पैरा 4 के मापदंडों का समाधान नहीं होता हो और इस तथ्य के होते हुए भी कि वे पैरा 4 के मापदंडों की पूर्ति करते हैं, उनके बारे में पैरा 5 के अध्यक्षीन कार्यवाही की जाती बताया गया है। दोनों ही मामलों में उदाहरणों की सम्पूर्ण सूची न देकर कुछेक आदर्शभूत मामलों की देना का प्रयास किया गया है। सहमति की सुगमता के उद्देश्य से,

इस जापन में संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 के नियम पारस्परिक रूप से लागू होंगे।

अनुच्छेद 12 में केवल कतिपय तकनीकी तथा परामर्शी सेवाओं को शामिल किया गया है। इस संदर्भ में, तकनीकी सेवाओं से हमारा अभिप्राय ऐसी सेवाओं से है जिनके लिए प्रौद्योगिकी में निपुणता अपेक्षित है। इस संदर्भ में परामर्शदात्री सेवाओं से हमारा अभिप्राय, परामर्शी सेवाओं से है। कुछ सीमा तक तकनीकी तथा परामर्शदात्री सेवाएं एक समान किस्म की होती हैं क्योंकि परामर्शदात्री सेवा तकनीकी सेवा भी हो सकती है लेकिन परामर्शदात्री सेवाओं की श्रेणी में कोई परामर्शी सेवा भी शामिल है चाहे उसे निष्पादित करने के लिए प्रौद्योगिकी में निपुणता अपेक्षित हो अथवा न हो।

पैराग्राफ 4 के अध्वधीन, तकनीकी तथा परामर्शदात्री सेवाओं को निम्नलिखित सीमा तक ही अंतर्विष्ट की गई सेवाएं समझा जाता है :-

1. पैरा 4 (क) में यथा-उल्लिखित यदि ऐसी सेवाएं किसी अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना, जिसके लिए किसी रायल्टी अदायगी की जाती है, को लागू करने अथवा उपभोग करने के लिए आनुवंशिक तथा सहायक रूप में हो ; अथवा (2) पैरा 4 (ख) में यथा उल्लिखित, यदि वे तकनीकी जानकारी अनुभव, विज्ञता, जानकारी अथवा प्रक्रियाएं उपलब्ध कराते हों, अथवा उनमें किसी तकनीकी योजना अथवा तकनीकी डिजाइन का विकास करने तथा अन्तर्गण का कार्य निहित हों,। इस प्रकार पैरा 4(ख) के अध्वधीन, ऐसी परामर्शदात्री सेवाएं जो तकनीकी स्वरूप की न हों, अंतर्विष्ट सेवाएं नहीं कही जा सकती हैं।

पैराग्राफ 4 (क)

अनुच्छेद 12 के पैरा 4 (क) में ऐसी तकनीकी अथवा परामर्शदात्री सेवाओं का उल्लेख किया गया है जो किसी अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना को लागू करने अथवा उपभोग करने के लिए आनुवंशिक तथा सहायक रूप में हों तथा जिनके लिए पैरा 3 (क) अथवा (ख) में उल्लिखित कोई अदायगी प्राप्त की जाती हो। इस प्रकार पैरा 4(क) में वे तकनीकी तथा परामर्शदात्री सेवाएं शामिल हैं जो किसी ऐसी अप्रत्यक्ष सेवाओं के प्रयोग अथवा उपभोग के लिए आनुवंशिक तथा सहायक होती हैं तथा जिनके लिए पैरा 3 (क) में यथा-उल्लिखित किसी लाइसेंस बित्री के अध्वधीन कोई रायल्टी प्राप्त होती है तथा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग अथवा उपभोग के लिए ऐसी आनुवंशिक तथा सहायक सेवाएं जिनके लिए पैरा 3(ख) में उल्लिखित किसी पट्टे के अध्वधीन कोई रायल्टी प्राप्त की गई हो।

यह सहमति हुई है कि किसी अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना, जिसके लिए पैरा 3 (क) अथवा (ख) में उल्लिखित

कोई सेवा धन प्रभार प्राप्त किया गया हो उसे "आनुवंशिक तथा सहायक" तभी माना जाएगा यदि ऐसी सेवा उक्त अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना के उपभोग अथवा उपयोग से संबंधित हो। इसके अलावा, ऐसी व्यवस्था ; जिसके अध्वधीन सेवा फीस तथा इस प्रकार की अन्य अदायगी की गई हैं, का प्रमुख स्पष्ट प्रयोजन यह होना चाहिए कि पैरा 3 में उल्लिखित अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना का उपयोग अथवा उपभोग किया गया है। इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या वह सेवा पैरा 3 में उल्लिखित उस अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना के उपयोग अथवा उपभोग से संबंधित है अथवा नहीं है, और क्या ऐसी व्यवस्था का प्रमुख स्पष्ट उद्देश्य ऐसे उपयोग अथवा उपभोग से है अथवा नहीं, इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों अथवा परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे निर्धारण (यह आवश्यक नहीं है कि वे नियंत्रणकारी हों) के संगत कारकों में निम्नलिखित कारक शामिल हैं :

1. संदर्भाधीन सेवाओं से पैरा 3 में उल्लिखित अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना के प्रभावी उपयोग अथवा उपभोग में किस सीमा तक सुविधा मिलती है ;

2. ऐसे कारोबारिक व्यवस्थाओं, जिनमें पैरा 3 में वर्णित रायल्टी दी जाती है, में आमतौर पर पारंपरिक रूप से इस प्रकार की सेवाएं किसी सीमा तक दी जाती हैं ;

3. क्या सेवाओं के लिए अदा की गई राशि (अथवा जिसका निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही पार्टियों द्वारा भुगतान किया जायेगा) पैरा 3 में उल्लिखित सेवाओं तथा अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना के लिए सम्मिलित रूप से की गई अदायगियों का एक अपर्याप्त भाग है ;

4. क्या पैरा 3 में उल्लिखित सेवाओं तथा रायल्टी के लिए की गई अदायगियों किसी सकल संविदा (अथवा संगत संविदाओं के किसी सेट) के तहत की जाती है ; और

5. क्या सेवाओं को निष्पादित करने वाला व्यक्ति ही अथवा पैरा 3 में उल्लिखित रायल्टियों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति है। इस प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को तभी परस्पर संबंधित समझा जाएगा यदि उनके संबंध का उल्लेख अनुच्छेद 9 (सहयोगी उद्यम) में किया गया हो अथवा यदि सेवाएं प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा कार्य किसी समग्र व्यवस्था के अंतर्गत कर रहा हो जिसमें रायल्टियों को अदा करने वाला तथा उन्हें प्राप्त करने वाला भी शामिल है।

इस सीमा तक ऐसी सेवाओं को किसी अधिकार, संपत्ति अथवा सूचना के उपयोग अथवा उपभोग के लिए आनुवंशिक तथा सहायक सेवाएं नहीं माना जाता है जिनके लिए पैरा 3 के अध्वधीन रायल्टी अदा की जाती है। ऐसी सेवाओं को मात्र उतनी सीमा तक ही "अंतर्विष्ट सेवाएं" माना जाएगा जिस सीमा तक पैरा 4 (ख) में इसका उल्लेख किया है।

उदाहरण (1)

तथ्य :

संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई विनिर्माता किसी भारतीय कंपनी को विनिर्माण के एंग प्रोसेस का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार प्रदान करता है जिसके लिए अंतरणकर्ता को प्रोसेस पेटेंट प्राप्त होने के कारण एकमात्र अधिकार प्राप्त है अथवा कानून के तहत प्रोसेस के स्वामी को अथवा सुरक्षा प्राप्त है। संविदाकारी व्यवस्था के एक भाग के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका का विनिर्माता भारतीय कंपनी को कुछेक परामर्शी सेवाएं देने के लिए राजी हो जाता है ताकि भारतीय कंपनी की प्रक्रियाओं के इस्तेमाल करने की विधि में कारगर ढंग से सुधार हो सके। ऐसी सेवाओं में उदाहरणार्थ जो सेवाएं शामिल हैं वे इस प्रकार हैं : विनिर्माण प्रोसेस के लिए आवश्यक सामग्री की सप्लाई के स्रोतों पर सूचना तथा मलाहू देने और विनिर्मित उत्पाद की बिक्री तथा सेवा साहित्य सामग्री के विकास के लिए सूचना तथा मलाहू देने की व्यवस्था। ऐसी सेवाओं के लिए की जा सकने वाली अदायगियां संविदाकारी व्यवस्था के अंतर्गत देव कुल प्रतिफल का एक महत्वपूर्ण भाग नहीं होंगी। क्या इन सेवाओं के लिए की गई अदायगियों "अंतर्विष्ट सेवाओं" के लिए फीस मानी जाएगी ?

विश्लेषण :

यह अदायगियों अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस हैं। इस उदाहरण में उल्लिखित सेवाएं कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त विनिर्माण प्रोसेस के इस्तेमाल की आनुवंशिक तथा सहायक सेवाएं हैं जैसा कि अनुच्छेद 12 के पैरा 3 (क) में उल्लेख किया गया है क्योंकि ये सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग अथवा उपयोग से संबंधित हैं तथा इस व्यवस्था का स्पष्ट रूप से प्रमुख उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से की गई इस व्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार प्रदान करना है। चूंकि ये सेवाएं विनिर्माण-प्रोसेस के इस्तेमाल की आनुवंशिक तथा सहायक सेवाएं हैं इसलिए इन सेवाओं की फीस को अनुच्छेद 12 के पैरा 4 (क) के अधधीन अंतर्विष्ट की गई सेवाओं के लिए फीस माना जाएगा चाहे ऐसी सेवाओं का उल्लेख पैरा 4 (ख) में किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो।

उदाहरण 2

तथ्य :

कोई भारतीय विनिर्माता कंपनी ऐसे किसी उत्पाद का उत्पादन करती है तो उसका निर्माण रोगाणुहीन करने की प्रती के अनुसार किया जाये तथा इस काम के लिए जिन मशीनों का उपयोग किया जाये उन्हें जीवाणु अथवा अन्य नुकसानदेह प्रस्तुतों से पूर्णतः मुक्त रखा जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी ने इस प्रकार की मशीनों से ऐसे हानिकर पदार्थों के जमाओं को हटाने के लिए सफाई करने की एक विशेष प्रक्रिया विकसित की है

संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ ऐसी संविदा करती है जिसके अधधीन पूर्ववर्ती कंपनी परमर्शी कंपनी की मशीनरी की नियमित आधार सफाई करेगी। इस व्यवस्था के एक भाग के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी भारतीय कंपनी को एक ऐसा उपस्कर पट्टे पर देती है जिससे भारतीय कंपनी अपनी मशीनरी में जमा हुई जीवाणुओं के लेवल को यह पता लगाने के लिए माप सके कि सफाई की आवश्यकता कब है ? क्या इन सेवाओं के लिए की गई अदायगियों को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस माना जाएगा ?

विश्लेषण :

इस उदाहरण में, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी द्वारा सफाई करने की सेवाएं प्रदान करना तथा निगरानी रखने के उपस्कर को किंगए पर देना परस्पर एक-दूसरे से संबंधित हैं। फिर भी, इस व्यवस्था का स्पष्ट रूप से प्रमुख उद्देश्य सफाई की सेवाओं की व्यवस्था करना है। इस प्रकार, यद्यपि, सफाई करने की सेवाओं को तकनीकी सेवाएं माना जा सकता है तथापि, इन सेवाओं को निगरानी रखने के उपस्कर को किंगए पर देने के लिए "आनुवंशिक तथा सहायक" के रूप में नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, पैरा 4 (क) के अर्थ के अंतर्गत सफाई करने की सेवाओं को "अंतर्विष्ट सेवाएं" नहीं माना जा सकता है।

पैरा 4 (ख)

अनुच्छेद 12 के पैरा 4 (ख) में ऐसी तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को तकनीकी जानकारी, अनुभव, विज्ञता, प्रौद्योगिकीय जानकारी अथवा प्रक्रियाएं उपलब्ध होती हों अथवा इसमें ऐसे व्यक्ति को किसी तकनीकी प्लान अथवा तकनीकी डिजाइन का विकास करने और अंतरित करना शामिल हो। (इस प्रयोजनार्थ सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का एजेंट, नामित व्यक्ति अथवा अंतरिती माना जाएगा) यह श्रेणी पैरा 4 (क) में उल्लिखित श्रेणी से अपेक्षाकृत सीमित है क्योंकि इसमें ऐसी सेवा शामिल नहीं है जिससे सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होती हो। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी को उस समय "उपलब्ध किया गया माना जाएगा" जब सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में सक्षम हों। यह तथ्य कि सेवा की आवश्यकता करना सेवा की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति द्वारा तकनीकी निविष्टि प्राप्त कर लेगा इसका स्वतः अर्थ नहीं है कि सेवाएं खरीदने वाले व्यक्ति को तकनीकी जानकारी, विज्ञता आदि पैरा 4 (ख) के अर्थ के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई थी। इसी प्रकार के ऐसे किसी उत्पाद के इस्तेमाल, जिसमें प्रौद्योगिकी शामिल हो, को स्वतः ही प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराया जाना नहीं माना जाएगा।

सेवाओं की प्रतीकात्मक श्रेणियों में, जिनमें सामान्यतया या तो तकनीकी प्लानों अथवा तकनीकी डिजायनों का विकास और अन्तरण शामिल होता है, अथवा पैरा 4 (ख) में यथा-उल्लिखित प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराना शामिल होता है, निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं :

1. इंजीनियरी सेवाएं (इसमें बायो-इंजीनियरिंग तथा वैमानिकी, कृषि, सीरम-रसायन, सिविल, विद्युतीय, मैकेनिकल, धातुकर्मीय तथा औद्योगिक इंजीनियरी की उपश्रेणियां शामिल हैं) ;

2. वास्तुशिल्पीय सेवाएं ; और

3. कम्प्यूटर साफ्ट वेयर का विकास ।

पैरा 4 (ख) के अध्वीन तकनीकी तथा परामर्शदात्री सेवाएं विभिन्न प्रकार के विन्यासों, कार्यकलापों तथा उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा सकती हैं उदाहरण के तौर पर ऐसी सेवाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में संबंधित हो सकती हैं :-

1. बायोतकनीकी सेवाएं ;
2. खाद्य संसाधन ;
3. पर्यावरण संबंधी तथा परिस्थिति विज्ञान संबंधी सेवाएं
4. सेटलाइट अथवा अन्यथा के माध्यम से संचार व्यवस्था ;
5. ऊर्जा संरक्षण ;
6. खनिज तेल अथवा खनिज गैस का समन्वेषण तथा समुपयोजन ;
7. भूगर्भीय सर्वेक्षण ;
8. वैज्ञानिक सेवाएं ; तथा
9. तकनीकी प्रशिक्षण ।

निम्नलिखित उदाहरणों से पैरा 4(ख) में उल्लिखित शर्तों के क्षेत्र विस्तार का संकेत मिलता है :-

उदाहरण 3 :

तथ्य :

संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी विनिर्माता को मकानों की भीतरी दीवारों के लिए बाल-बोर्ड का विनिर्माण करने की प्रक्रिया के इस्तेमाल में अनुभव प्राप्त है जोकि इस प्रकार के मानक उत्पादों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ है । कोई भारतीय भवन-निर्माता उत्पाद का अपने इस्तेमाल के लिए उत्पादन करना चाहता है । वह एक संयंत्र किराए पर लेता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी के साथ यह संविदा करता है कि वह कंपनी भारतीय कंपनी के इंजीनियरों को यह दिखाने के लिए भारत में अपने विशेषज्ञ भेजे कि अधिक मजबूती वाले बाल-बोर्ड का किस प्रकार निर्माण किया जा सकता है । संयुक्त राज्य अमेरिका का ठेकेदार तकनीशियनों सहित भारतीय फर्म में कुछ महीने कार्य करता है । क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐसी फर्मों को

की गई अदायगियों को "अंतर्विष्ट सेवाओं" के लिए अदायगियां समझा जाता है ?

विश्लेषण :

ऐसी अदायगियां अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस होंगी । ये सेवाएं तकनीकी अथवा परामर्श स्वरूप की होंगी क्योंकि इनमें दोनों ही सेवाओं के प्रकार के घटक या कारक होंगे । इन सेवाओं से भारतीय कंपनी को तकनीकी जानकारी, विज्ञता तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध होंगी ।

उदाहरण 4 :

तथ्य :

संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई विनिर्माता भारत से बाहर किसी अन्य देश में बाल-बोर्ड के फेब्रिकेशन का संयंत्र चलाता है । भारत का कोई भवन-निर्माता उक्त संयंत्र में बाल-बोर्ड के उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी को सेवाएं फीस पर किराए पर लेता है । भारतीय कंपनी कच्चा माल उपलब्ध कराती है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का विनिर्माता अत्यंत विकसित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अपने संयंत्र में उक्त बाल-बोर्ड की संविरोचना करता है । क्या उदाहरण इस में उल्लिखित फीस को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए अदायगियां समझा जाएगा ?

विश्लेषण :

उक्त फीस को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए नहीं माना जाएगा । यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी स्पष्ट रूप से तकनीकी सेवाएं निष्पादित कर रही है, तथापि भारतीय कंपनी को न तो कोई तकनीकी जानकारी, विज्ञता आदि उपलब्ध कराई गई थी और न ही किसी तकनीकी प्लान अथवा डिजाइन का किसी प्रकार का विकास तथा अंतरण किया गया था । संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी मात्र संविदा में उल्लिखित विनिर्माणकारी सेवाओं को निष्पादित कर रही है ।

उदाहरण 5 :

तथ्य :

कोई भारतीय फर्म समस्त भारत में फैले हुए उसके खुदरा बिक्री केन्द्रों की श्रृंखलाओं में इस्तेमाल के लिए माल-सूची नियंत्रण साफ्ट वेयर की स्वामिनी है । यह कंपनी के साज-सामान की बिक्री के लिए देश भर में इधर-उधर घूम-घूम कर सामान बेचने के लिए ट्रेवलिंग सेल्समैनों के एक दल की नियुक्ति करके अपने बिक्री-संकायों का विस्तार करती है । कंपनी अपने साफ्टवेयर में संशोधन करना चाहती है ताकि वे सेल्समैन कंपनी के केन्द्रीयकृत कंप्यूटर से यह सूचना प्राप्त कर सकें कि माल सूची में कौन-सा उत्पाद उपलब्ध है और उक्त उत्पाद की डिलीवरी कब की जा सकती है । भारतीय फर्म इस प्रयोजनार्थ अपने साफ्टवेयर में संशोधन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कोई

कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग फर्म किराए पर लेती है। क्या भारतीय फर्म द्वारा अदा की गई फीस को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस समझा जाएगा?

विश्लेषण :

यह फीस अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी स्पष्ट रूप से भारतीय कंपनी को तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है और वह भारतीय कंपनी को उस तकनीकी प्लान (अर्थात् कम्प्यूटर प्रोग्राम) को अंतरित करती है जिसे उसने विकसित किया है।

उदाहरण 6 :

तथ्य :

वनस्पति तेल का विनिर्माण करने वाली कोई भारतीय कंपनी किसी ऐसे सयत्न से कोलेस्ट्रॉल मुक्त तेल का उत्पादन करना चाहती है जो सामान्यतया कोलेस्ट्रॉल वाले तेल का उत्पादन करता है। किसी अमेरिकी कंपनी ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिसके द्वारा तेल में से कोलेस्ट्रॉल को शोधित किया जाता है। भारतीय कंपनी अपने फार्मूले में सुधार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी के साथ संविदा करती है ताकि कोलेस्ट्रॉल को दूर किया जा सके तथा नए फार्मूले का उपयोग करने के लिए भारतीय कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। क्या भारतीय कंपनी द्वारा अदा की गई फीस को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए अदा की गई फीस माना जाएगा।

विश्लेषण :

ऐसी फीस को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस माना जाएगा। ये सेवाएं तकनीकी स्वरूप की हैं तथा तकनीकी जानकारी भारतीय कंपनी को उपलब्ध कराई गई है।

उदाहरण 7 :

तथ्य :

वनस्पति तेल का विनिर्माण करने वाली भारतीय फर्म को कोलेस्ट्रॉल मुक्त तेल का उत्पादन करने की विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त हो गई है तथा वह अपने उत्पादों का विपणन विश्व-व्यापी आधार पर करना चाहती है। यह कंपनी ऐसे तेल के लिए विश्व के बाजार का कम्प्यूटर द्वारा अनुरोध करने तथा कंपनी की विपणन नीतियों पर सलाह देने के लिए अमेरिका की किसी विपणन परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं किराए पर लेती है क्या उक्त अमेरिकी कंपनी को अदा की गई फीस अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस मानी जाएगी?

विश्लेषण :

यह फीस अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए नहीं है। अमेरिकी कंपनी परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध करा रही है जिसमें तकनीकी निपुणता तथा विशेषज्ञता सेवा का पर्याप्त रूप से इस्तेमाल करना शामिल है। लेकिन, यह कंपनी भारतीय

कंपनी को किसी भी प्रकार से तकनीकी अनुभव, जानकारी अथवा निपुणता आदि उपलब्ध नहीं करा रही है और न ही किसी तकनीकी प्लान अथवा डिजाइन का अंतरण कर रही है। भारतीय कंपनी सेवा को विषयक ठेके के माध्यम से जो अंतरित किया गया है, वह वाणिज्यिक सूचना है। इस तथ्य को देखते हुए कि वाणिज्यिक सूचना विषयक सेवा को निष्पादित करने के उद्देश्य से सेवा के निष्पादनकर्ता को तकनीकी निपुणता लेना अपेक्षित था, ऐसी सेवा को पैरा 4 (ख) के अभिप्राय के अंतर्गत तकनीकी सेवा नहीं कहा सकता है।

पैरा 5 :

अनुच्छेद 12 के पैरा 5 में अनेक सेवा श्रेणियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें अंतर्विष्ट सेवाएं नहीं माना गया है, भले ही वे सेवाएं पैरा 4 के मापदण्डों को पूरा करती हों। नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनमें दी गई फीस को पैरा 4 के अध्याधीन शामिल किया गया है लेकिन उन्हें पैरा 5 में उल्लिखित शर्तों के कारण छोड़ दिया गया है।

उदाहरण 8 :

तथ्य :

कोई भारतीय कंपनी किसी अमेरिका कम्प्यूटर विनिर्माता से किसी कम्प्यूटर की खरीद करती है। खरीद-करार के एक अंगरूप में वह विनिर्माता कम्प्यूटर का विन्यास करने तथा परिचालन-प्रणाली को स्थापित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो जाता है कि भारतीय कंपनी का स्टाफ उस कम्प्यूटर के संचालन में सक्षम है। इसके अतिरिक्त खरीद-करार के एक अंगरूप में भी विक्रेता संचालन-प्रणाली को अद्यतन करने तथा अद्यतन प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के निमित्त दस वर्षों की अवधि के लिए सहमत हो जाता है। संविदा में उल्लिखित सेवाओं के ये दोनों कारक पैरा 4 (ख) के अध्याधीन माने जाएंगे और ये अंतर्विष्ट सेवाएं होंगी। क्या इनमें से किसी एक सेवा अथवा दोनों सेवाओं को पैरा 5 (क) के अध्याधीन अंतर्विष्ट सेवाओं की श्रेणियों में शामिल न किया जाए क्योंकि ये सेवाएं आनुपंगिक तथा सहायक स्वरूप की हैं तथा इसके साथ-साथ कम्प्यूटर की बिक्री से जुटिल और अनिवार्य रूप से संबद्ध हैं।

विश्लेषण :

कम्प्यूटर की स्थापना में सहायता करना तथा आरंभिक प्रशिक्षण देना। कम्प्यूटर की बिक्री के लिए आनुपंगिक तथा सहायक सेवाएं हैं और ये सेवाएं बिक्री से जुटिल तथा अनिवार्य रूप से संबंधित हैं। इन सेवाओं के बिना भारतीय खरीददार के लिए कम्प्यूटर का महत्व बिल्कुल नगण्य रह जाएगा जिन्हें विक्रेता ठार, तुरंत तथा लाभप्रद रूप से उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए कम्प्यूटर की स्थापना में सहायता करने तथा आरंभिक प्रशिक्षण के लिए अदा की गई

फीस को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इन सेवाओं को प्रदान करना प्रबंध व्यवस्था का प्रमुख प्रयोजन नहीं है।

संचालन प्रणाली को अद्यतन बनाने तथा इसके लिए आवश्यक सहसम्बद्ध प्रशिक्षण देने से संबंधित सेवाएं कंप्यूटर की बिक्री के निमित्त आनुषंगिक तथा सहायक सेवाएं हो सकती हैं लेकिन ये सेवाएं बिक्री से जटिल तथा अनिवार्य रूप से संबद्ध नहीं हैं। कंप्यूटर को अपग्रेड किए बिना वह उसी प्रकार कार्य करता रहेगा जिस प्रकार वह खरीद के समय कार्य कर रहा था और इस प्रकार वह उसी प्रकार के कार्य ही निष्पादित करता रहेगा। इसलिए अद्यतन को प्राप्त किए जाने के कार्य को कंप्यूटर की बिक्री से जटिल रूप से तथा अनिवार्य रूप से संबद्ध नहीं कहा जा सकता है।

उदाहरण 9 :

तथ्य :

कोई भारतीय अस्पताल किसी अमेरिकी विनिर्माता से एक्स-रे की मशीन खरीदता है। खरीद-करार के अंग-रूप में वह विनिर्माता किसी आरंभिक जांच-पड़ताल के लिए भारत में मशीन की स्थापना करने, मशीन के इस्तेमाल के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा सामान्य वारंटी अवधि (दो वर्ष) के दौरान मशीन की आवश्यक आधार पर सर्विस करने के लिए सहमत हो जाता है। अस्पताल द्वारा खरीदी गई किसी वैकल्पिक सेवा संविदा के अध्यक्षीन विनिर्माता मशीन की संपूर्ण कार्य-विधि के दौरान कतिपय अन्य ऐसी सर्विस करने के लिए भी सहमत हो जाता है जिसमें आवश्यक आधार पर जांच-पड़ताल करना तथा मरम्मत करने संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा अस्पताल को एक्स-रे की फिल्मों अथवा तकनीकों में हुए ऐसे विकासों के बारे में सलाह देना भी शामिल है, जिनमें मशीन की कार्यक्षमता में सुधार किया जा सकता है तथा उन नए विकासों को लागू करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। एक्स-रे मशीन की लागत की तुलना में मशीन की आरंभिक स्थापना करने, जांच-पड़ताल करने, प्रशिक्षण देने तथा वारंटी सेवा की लागत अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। क्या उपर्युक्त कोई भी सेवा एक्स-रे मशीन की बिक्री की आनुषंगिक तथा सहायक सेवा है और जटिल तथा अनिवार्य रूप से संबद्ध है?

विश्लेषण :

भारत में मशीन की आरंभिक स्थापना करना, जांच-पड़ताल करना तथा प्रशिक्षण की सेवाएं देना और वारंटी अवधि के दौरान आवश्यक आधार पर सेवाएं देना, एक्स-रे मशीन की बिक्री की आनुषंगिक तथा सहायक सेवाएं हैं और बिक्री से जटिल तथा अनिवार्य रूप से संबद्ध हैं, क्योंकि अस्पताल को इस मशीन की उपयोगिता इन सेवाओं पर ही

निर्भर करती है और इस अवधि के दौरान मशीन के संबंध में विनिर्माता की पूर्ण जिम्मेवारी होती है तथा इन सेवाओं की लागत संविदा की धनराशि का अपेक्षाकृत एक बहुत ही कम भाग है। इसलिए, पैरा 5 (क) के अध्यक्षीन इन फीसों को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस नहीं माना जा सकता है, भले ही ये सेवाएं पैरा 4 (ख) के अध्यक्षीन अन्यथा न आती हों।

न तो वारंटी अवधि के पश्चात् जांच-पड़ताल करना और मरम्मत विषयक सेवाएं प्रदान करना और न ही नए विकासों के बारे में सलाह-मशविरा देना और प्रशिक्षण की सेवाएं देना एक्स-रे मशीन की आरंभिक खरीद से "जटिल तथा अनिवार्य" रूप से संबद्ध है। तदनुसार, इन सेवाओं के लिए दी गई फीस को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस माना जाएगा यदि वे पैरा 4 (ख) के मानदण्डों को पूरा करती हैं।

उदाहरण 10 :

तथ्य :

आटोमोबाइल का कोई भारतीय विनिर्माता अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करके हैलीकॉप्टरों के विनिर्माण करने का निर्णय लेता है। वह विनिर्माता वैमानिकी इंजीनियरी का अध्ययन करने के लिए मैसाचूसेट्स तकनालाजी संस्थान (एम. आई. टी.) द्वारा आयोजित किए जाने वाले दो वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अपने डिजाइन कर्मचारियों में से इंजीनियरों का एक समूह भेजता है। भारतीय फर्म अपनी फर्म के कर्मचारियों की ओर से मैसाचूसेट्स तकनालाजी संस्थान (एस. आई. टी.) को ट्यूशन फीस की अदायगी करती है। क्या इस प्रकार की ट्यूशन फीस को अनुच्छेद 12 के अभिप्राय के अंतर्गत अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस माना जाएगा?

विश्लेषण :

ट्यूशन फीस दिए जाने के पीछे स्पष्ट रूप से मंशा फर्म के लिए तकनीकी सेवाओं को प्राप्त करना है लेकिन अदा की गई फीस किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा किए जा रहे अध्यापन के लिए है और इसलिए पैरा 5 (ग) के अध्यक्षीन इसे अंतर्विष्ट सेवा नहीं माना जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ यह कहना असंगत है कि क्या मैसाचूसेट्स तकनालाजी संस्थान (एम. आई. टी.) इस पाठ्यक्रम का आयोजन अपने परिसर में करता है अथवा किसी अन्य स्थल पर करता है।

उदाहरण 11 :

तथ्य :

जैसा कि उदाहरण (10) में कहा गया है, आटोमोबाइल का विनिर्माता अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करके हैलीकॉप्टरों का विनिर्माण करना चाहता है और वह वैमानिकी इंजीनियरी का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसी

भारतीय विश्वविद्यालय से संपर्क करता है। उक्त विश्वविद्यालय हैलीकॉप्टर बनाने वाले किसी अमेरिकी विनिर्माता से यह संविदा करता है कि वह विनिर्माता एक वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के संकाय हेतु किसी इंजीनियर को वैमानिकी इंजीनियरी के अतिथि प्रोफेसर के रूप में भेजे। क्या विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापन की ऐसी सेवाओं के लिए भ्रदा की गई धनराशि को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस माना जाएगा ?

विश्लेषण :

यह फीस किसी शैक्षिक संस्थान में अध्यापन के लिए दी गई है। इसलिए, पैरा 5 (ग) के अनुसार इस फीस को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस नहीं माना जा सकता है।

उदाहरण 12 :

तथ्य :

कोई भारतीय, प्रकाश व्यवस्था, तापन तथा वातानुकूलन, स्टीरियो साउंड प्रणाली तथा चोरी और अग्नि एलार्म प्रणाली पर नियंत्रण रखने हेतु अपने निवास पर कोई कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करना चाहता है। वह व्यक्ति आवश्यक वायरिंग प्रणाली ब्रिडाइट स्टैण्डर्ड साफ्टवेयर का डिजाइन तैयार करने तथा इस प्रणाली की स्थापना करने के लिए अनुदेशन आदि उपलब्ध कराने हेतु किसी अमेरिकी वैश्वव्यापक इंजीनियरिंग फर्म की सेवाएं किराए पर लेता है। क्या भारतीय व्यक्ति द्वारा अमेरिकी फर्म को भ्रदा की गई फीस अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस मानी जाएगी ?

विश्लेषण :

जिन सेवाओं के संबंध में फीस भ्रदा की जाती है, वे इस प्रकार की होती हैं जिन्हें पैरा 4 (ख) के अध्वधीन सामान्यतया अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस माना जाता है। लेकिन, चूंकि ये सेवाएं भ्रदायगी करने वाले व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हैं, इसलिए पैरा 5 (घ) के अध्वधीन ऐसी भ्रदायगियों को अंतर्विष्ट सेवाओं के लिए फीस नहीं माना जायेगा।

[अधिसूचना नं. 8786 (फा. सं. 501/2/74 एफ टी डी)]

एन. सी. जैन, संयुक्त सचिव

INCOME-TAX

G.S.R. 992(E).—Whereas the annexed Convention between the Govt. of the United States of America and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 18th December 1990, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Convention in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

Further, in exercise of the powers conferred by section 44A (b) of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) and section 44(b) of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Government also directs that the provisions of Article 28 of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEX

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the United States of America, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows :

ARTICLE 1

General Scope

1. This Convention shall apply to persons who are residence of one or both of the Contracting States, except as otherwise provided in the Convention.

2. The Convention shall not restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded :

(a) by the laws of either Contracting State; or

(b) by any other agreement between the Contracting States.

3. Notwithstanding any provision of the Convention except paragraph 4, a Contracting State may tax its residence [as determined under Article 4 (Residence)] and by reason of citizenship may tax its citizens, as if the Convention had not come into effect. For this purpose, the term "citizen" shall include a former citizen who loss of citizenship had as one of its principal purposes the avoidance of tax, but only for a period of 10 years following such loss.

4. The provisions of paragraph 3 shall not affect

(a) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 9 (Associated Enterprises), under paragraphs 2 and 6 of Article 20 (Private Pensions, Annuities, Alimony, and Child Support), and under Articles 25 (Relief From Double Taxation), 26 (Non-Discrimination), and 27 (Mutual Agreement Procedure); and

(b) the benefits conferred by a Contracting State under Articles 19 (Remuneration and Pensions in Respect of Government Service),

21 (Payments Received by Students and Apprentices), 22 (Payments Received by Professors, Teachers and Research Scholars) and 29 (Diplomatic Agents and Consular Officers), upon individuals who are neither citizens of, nor have immigrant status in, that State.

ARTICLE 2

Taxes Covered

1. The existing taxes to which this Convention shall apply are :

- (a) in the United States, the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but excluding the accumulated earnings tax, the personal holding company tax, and social security taxes), and the excise taxes imposed on insurance premiums paid to foreign insurers and with respect to private foundations (hereinafter referred to as "United States tax"); provided, however, the Convention shall apply to the excise taxes imposed on insurance premium paid to foreign insurers only to the extent that the risks covered by such premiums are not re-insured with a person not entitled to exemption from such taxes under this or any other Convention which applies to these taxes; and

(b) in India :

- (i) the income tax including any surcharge thereon, but excluding income tax on undistributed income of companies, imposed under the Income-tax Act; and

(ii) the surtax

(hereinafter referred to as "Indian tax").

Taxes referred to in (a) and (b) above shall not include any amount payable in respect of any default or omission in relation to the above taxes or which represent a penalty imposed relating to those taxes.

2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws and of any official published material concerning the application of the Convention.

ARTICLE 3

General Definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air-space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;

- (b) the term "United States", when used in a geographical sense means all the territory of the United States of America, including its territorial sea, in which the laws relating to United States tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and soil thereof, over which the United States has jurisdiction in accordance with international law and in which the laws relating to United States tax are in force;

- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or the United States as the context requires;

- (d) the term "tax" means Indian tax or United States tax, as the context requires;

- (e) the term "person" includes an individual, an estate, a trust, a partnership, a company, any other body of persons, or other taxable entity;

- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;

- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

- (h) the term "competent authority" means, in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative, and in the case of the United States, the Secretary of the Treasury or his delegate;

- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State;

- (j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places within the other Contracting State;

- (k) the term "taxable year" in relation to Indian Tax means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 27 (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

ARTICLE 4

Residence

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax

therein by reason of his domicile, residence, citizenship, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature, provided, however, that

- (a) this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State; and
- (b) in the case of income derived or paid by a partnership, estate, or trust, this term applies only to the extent that the income derived by such partnership, estate, or trust is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where, by reason of paragraph 1, a company is a resident of both Contracting States, such company shall be considered to be outside the scope of this Convention except for purposes of paragraph 2 of Article 10 (Dividends), Article 26 (Non-Discrimination), Article 27 (Mutual Agreement Procedure), Article 28 (Exchange of Information and Administrative Assistance) and Article 30 (Entry Into Force).

4. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual or a company is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement and determine the mode of application of the Convention to such person.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) a store or premises used as a sales outlet;
- (j) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources, but only if so used for a period of more than 120 days in any twelve month period;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than 120 days in any twelve month period;

(1) the furnishing of services other than included services as defined in Article 12 (Royalties and Fees for Included Services), within Contracting State by an enterprise through employees or other personnel, but only if :

- (i) activities of that nature continue within that State for a period or periods aggregating more than 90 days within any twelve-month period; or
- (ii) the services are performed within that State for a related enterprise (within the meaning of paragraph 1 of Article 9 (Associated Enterprises)).

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include any one or more of the following :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display, or occasional delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods

or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

- (c) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for other activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State if:

- (a) he has and habitually exercises in the first-mentioned State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make that fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;
- (b) he has no such authority but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, and some additional activities conducted in that State on behalf of the enterprise have contributed to the sale of the goods or merchandise; or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise and the transactions between the agent and the enterprise are not made under arm's-length conditions, he shall not be considered an agent of independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income From Immovable Property (Real Property)

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (real property), including income from agriculture or forestry situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in the other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in the other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly at arm's-length with the enterprise of which it is a permanent establishment and other enterprises controlling, controlled by or subject to the same common control as that enterprise. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis. The estimate adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including a reasonable allocation of executive and general administrative expenses, research and development expenses, interest, and other expenses incurred for the purposes of the enterprise as a whole (or the part thereof which includes the permanent establishment), whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than

toward reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than toward reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of this Convention, the profits to be attributed to the permanent establishment as provided in paragraph 1(a) of this Article shall include only the profits derived from the assets and activities of the permanent establishment and shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of the Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

7. For the purposes of the Convention, the term "business profits" means income derived from any trade or business including income from the furnishing of services other than included services as defined in Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) and including income from the rental of tangible personal property other than property described in paragraph 3 (b) of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services).

ARTICLE 8

Shipping and Air Transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including :—

- (a) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises ;

- (b) other activity directly connected with such transportation ; and
- (c) the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly connected with such transportation.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

5. For the purposes of this Article interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 (Interest) shall not apply in relation to such interest.

6. Gains derived by an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the alienation of ships, aircraft or containers owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that State, shall be taxed only in that State.

ARTICLE 9

Associated Enterprises

1. Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State : or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which, but for those conditions, would have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on

those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed :—

(a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 10 per cent of the voting stock of the company paying the dividends ;

(b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Sub-paragraph (b) and not sub-paragraph (a) shall apply in the case of dividends paid by a United States person which is a Regulated Investment Company. Sub-paragraph (a) shall not apply to dividends paid by a United States person which is a Real Estate Investment Trust, and sub-paragraph (b) shall only apply if the dividend is beneficially owned by an individual holding a less than 10 per cent interest in the Real Estate Investment Trust. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, income from other corporate rights which are subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident; and income from arrangements, including debt obligations, carrying the right to participate in profits, to the extent so characterized under the laws of the Contracting State in which the income arises.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the dividends are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not

impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed :

(a) 10 per cent of the gross amount of the interest if such interest is paid on a loan granted by a bank carrying on a bona fide banking business or by a similar financial institution (including an insurance company); and

(b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting State:

(a) and derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, a political subdivision or local authority thereof, the Reserve Bank of India, or the Federal Reserve Banks of the United States, as the case may be, and such other institutions of either Contracting State as the competent authorities may agree pursuant to Article 27 (Mutual Agreement Procedure);

(b) with respect to loans or credits extended or endorsed

(i) by the Export Import Bank of the United States, when India is the first-mentioned Contracting State; and

(ii) by the EXIM Bank of India, when the United States is the first-mentioned Contracting State; and

(c) to the extent approved by the Government of that State, and derived and beneficially owned by any person, other than a person referred to in sub-paragraphs (a) and (b), who is a resident of the other Contracting State, provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this behalf by the Government of the first-mentioned Contracting State;

shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Convention means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities, and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such securities, bonds, or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of the Convention. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 10 (Dividends).

5. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, though a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the interest is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political subdivision, local authority, or resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

ARTICLE 12

Royalties and Fees for Included Services

1. Royalties and fees for included services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for included services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State; but if the beneficial owner of the royalties or fees for included services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed :—

- (a) in the case of royalties referred to in subparagraph (a) of paragraph 3 and fees for included services as defined in this Article other than services described in subparagraph (b) of this paragraph :—
 - (i) during the first five taxable years for which this Convention has effect,
 - (A) 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services as defined in this Article, where the payer of the royalties or fees is the Government of that Contracting State, a political subdivision or a public sector company ; and
 - (B) 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services in all other cases ; and
 - (ii) during the subsequent years, 15 per cent of the gross amount of royalties or fees for included services ; and
- (b) in the case of royalties referred to in subparagraph (b) of paragraph 3 and fees for included services as defined in this Article that are ancillary and subsidiary to the enjoyment of the property for which payment is received under paragraph 3 (b) of this Article, 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services.

3. The term "royalties" as used in this Article means :—

- (a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic, or scientific work, including cinematograph films or work on film, tape or other means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting, any patent trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, including gains derived from the alienation of any such right or property which are contingent on the productivity, use, or disposition thereof; and
- (b) payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial, or scientific equipment, other than payments derived by an enterprise described in paragraph 1 of Article 8 (Shipping and Air Transport) from activities described in paragraph 2(c) or 3 of Article 8.

4. For purposes of this Article, "fees for included services" means payments of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or

consultancy services (including through the provision of services of technical or other personnel) if such services :—

- (a) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in paragraph 3 is received; or
- (b) make available technical knowledge, experience, skill, know-how or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.

5. Notwithstanding paragraph 4, "fees for included services" does not include amounts paid :

- (a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property other than a sale described in paragraph 3 (a);
- (b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;
- (c) for teaching in or by educational institutions ;
- (d) for services for the personal use of the individual or individuals making the payment; or
- (e) to an employee of the person making the payments or to any individual or firm of individuals (other than a company) for professional services as defined in Article 15 (Independent Personal Services).

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for included services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the royalties or fees for included services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the royalties or fees for included services are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

7. (a) Royalties and fees for included services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority, or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for included services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for included services was incurred, and such royalties or fees for included services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for included services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated

(b) Where under sub-paragraph (a) royalties or fees for included services do not arise in one of the Contracting States, and the royalties relate to the use of or the right to use the right or property, or the fees for included services relate to services performed, in one of the Contracting States, the royalties or fees for included services shall be deemed to arise in that Contracting State.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for included services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

ARTICLE 13

Gains

Except as provided in Article 8 (Shipping and Air Transport) of this Convention, each Contracting State may tax capital gains in accordance with the provisions of its domestic law.

ARTICLE 14

Permanent Establishment Tax

1. A company which is a resident of India may be subject in the United States to a tax in addition to the tax allowable under the other provision of this Convention.

(a) Such tax, however, may be imposed only on :

- (i) the portion of the business profits of the company subject to tax in United States which represents the dividend equivalent amount ; and
- (ii) the excess, if any, of interest deductible in the United States in computing the profits of the company that are subject to tax in the United States and either attributable to a permanent establishment in the United States or subject to tax in the United States under Article 6 [Income from Immovable Property (Real Property)], Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) as fees for included services, or Article 13 (Gains, of this Convention over the interest paid by or from the permanent establishment or trade or business in the United States.

(b) For purposes of this article, business profits means profits that are effectively connected (or treated as effectively connected) with the conduct of a trade or business within the United States and are either attributable to a permanent establishment in the United States or subject to tax in the United States under Article 6 [Income from Immovable Property (Real Property)], Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) as fees for included services or Article 13 (Gains) of this Convention.

(c) The tax referred to in sub-paragraph (a) shall not be imposed at a rate exceeding :—

- (i) the rate specified in paragraph 2 (a) of Article 10 (Dividends) for the tax described in sub-paragraph (a) (i); and
- (ii) the rate specified in paragraph 2 (a) or (b) (whichever is appropriate) of Article 11 (Interest) for the tax described in sub-paragraph (a) (ii).

2. A company which is a resident of the United States may be subject to tax in India at a rate higher than that applicable to the domestic companies. The difference in the tax rate shall not, however, exceed the existing difference of 15 percentage points.

3. In the case of banking company which is a resident of the United States, the interest paid by the permanent establishment of such a company in India to the head office may be subject in India to a tax in addition to the tax imposable under the other provisions of this Convention at a rate which shall not exceed the rate specified in paragraph 8 (a) of Article 11 (Interest).

ARTICLE 15

Independent Personal Services

1. Income derived by a person who is an individual or firm of individuals (other than a company) who is a resident of a Contracting State from the performance in the other Contracting State of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in the first-mentioned State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if such person has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if the person's stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days in the relevant taxable year.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 16

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 17 (Directors' Fees), 18 (Income Earned by Entertainers and Athletes), 19 (Remuneration and Pensions in respect of Government Service), 20 (Private Pensions, Annuities, Alimony, and Child Support), 21 (Payments Received by Students and Apprentices) and 22 (Payments Received by Professors, Teachers and

Research Scholars), salaries, wages, and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant taxable year;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base or a trade or business which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

ARTICLE 17

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 18

Income Earned by Entertainers and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 (Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal Services), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State, except where the amount of the net income derived by such entertainer or athlete from such activities (after deduction of all expense incurred by him in connection with his visit and performance) does not exceed one thousand five hundred United States dollars (\$ 1,500) or its equivalent in Indian rupees for the taxable year concerned.

2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete but to another person, that income of that other person may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business Profits), 15 (Independent Personal Services)

and 16 (Dependent Personal Services), be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised unless the entertainer, athlete, or other person establishes that neither the entertainer or athlete nor persons related thereto participate directly or indirectly in the profits or that other person in any manner, including the receipt of deferred remuneration, bonuses, fees, dividends, partnership distributions, or other distributions.

3. Income referred to in the preceding paragraphs of this Article derived by a resident of a Contracting State in respect of activities exercised in the other Contracting State shall not be taxed in that other State if the visit of the entertainers or athletes to that other State is supported wholly or substantially from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting State, or of a political sub-division or local authority thereof.

4. The competent authorities of the Contracting States may, by mutual agreement, increase the dollar amounts referred to in paragraph 1 to reflect economic or monetary developments.

ARTICLE 19

Remuneration and Pensions in Respect of Government Service

1 (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that state or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 16 (Dependent Personal Services), 17 (Directors' Fees), 18 (Income Earned by Entertainers and Athletes) and 20 (Private Pensions, Annuities, Alimony and Child Support) shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

ARTICLE 20

Private Pensions, Annuities, Alimony and Child Support

1. Any pension, other than a pension referred to Article 19 (Remuneration and Pensions) in Respect of Government (Service), or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. Notwithstanding paragraph 1, and subject to the provisions of Article 19 (Remuneration and Pensions in respect of Government Service), social security benefits and other public pensions paid by a Contracting State to a resident of the other Contracting State or a citizen of the United States shall be taxable only in the first-mentioned State.

3. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

4. The term "annuity" means stated sums payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable number of years, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth (but not for services rendered).

5. Alimony paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. The term "alimony" as used in this paragraph means periodic payments made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, which payments are taxable to the recipient under the laws of the State of which he is a resident.

6. Periodic payments for the support of a minor child made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance or compulsory support, paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

ARTICLE 21

Payments Received by Students and Apprentices

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State principally for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State, on payments which arise outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training.

2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

3. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken.

4. For the purposes of this Article, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the taxable year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding taxable year.

ARTICLE 22

Payments Received by Professors, Teachers and Research Scholars

1. An individual who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or engaging in research at a university, college or other recognized educational institution in that State, and who was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempted from tax by the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date he first visits that State for such purpose.

2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

ARTICLE 23

Other Income

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 [Income from Immovable Property (Real Property)], if the beneficial owner of the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the income is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 24

Limitation on Benefits

1. A person (other than an individual) which is a resident of a Contracting State and derives income from the other Contracting State shall be entitled under this Convention to relief from taxation in that other Contracting State only if :

- (a) more than 50 per cent of the beneficial interest in such person (or in the case of a company more than 50 per cent of the number of shares of each class of the company's shares) is owned, directly or indirectly, by one or more individual residents of one of the Contracting States, one of the Contracting States or its political sub-divisions or local authorities, or other individuals subject to tax in either Contracting State on their worldwide incomes, or citizens of the United States; and
- (b) the income of such person is not used in substantial part, directly or indirectly, to meet liabilities (including liabilities for interest or royalties) to persons who are not residents of one of the Contracting States, one of the Contracting States or its political sub-divisions or local authorities, or citizens of the United States.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the income derived from the other Contracting State is derived in connection with, or is incidental to, the activity conducted by such person of a trade or business in the first-mentioned State (other than the business of making or managing investments, unless these activities are banking or insurance activities carried out by a bank or insurance company).

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the person deriving the income is a company which is a resident of a Contracting State in whose principal class of shares there is substantial and regular trading on a recognized stock exchange. For purposes of the preceding sentence, the term "recognized stock exchange" means :

- (a) in the case of the United States, the NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange registered with the Securities and Exchange Commission as a national securities exchange for purposes of the Securities Act of 1934;
- (b) in the case of India, any stock exchange which is recognized by the Central Government under the Securities Contracts Regulation Act, 1956; and
- (c) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

4. A person that is not entitled to the benefits of this Convention pursuant to the provisions of the preceding paragraphs of this Article may, nevertheless, be granted the benefits of the Convention if the competent authority of the State in which the income in question arises so determines.

ARTICLE 25

Relief From Double Taxation

1. In accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income :

- (a) the income tax paid to India by or on behalf of such citizen or resident; and
- (b) in the case of a United States company owning at least 10 per cent of the voting stock of a company which is a resident of India and from which the United States company receives dividends, the income tax paid to India by or on behalf of the distributing company with respect to the profits out of which the dividends are paid.

For the purposes of this paragraph, the taxes referred to in paragraph (1b) and 2 of Article 2 (Taxes Covered) shall be considered income taxes.

- 2.(a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the United States, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the United States, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in the United States.

- (b) Further, where such resident is a company by which a surtax is payable in India the deduction in respect of income tax paid in the United States shall be allowed in the first instance from income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.

3. For the purposes of allowing relief from double taxation pursuant to this Article, income shall be deemed to arise as follows :

- (a) income derived by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention (other than solely by reason of citizenship in accordance with paragraph 3 of Article 1 (General Scope)) shall be deemed to arise in that other State;
- (b) income derived by a resident of a Contracting State which may not be taxed in the other Contracting State in accordance with the Convention shall be deemed to arise in the first-mentioned State.

Notwithstanding the preceding sentence, the determination of the source of income for purposes of this Article shall be subject to such source rules in the domestic laws of the Contracting States as apply for the purpose of limiting the foreign tax credit. The

preceding sentence shall not apply with respect to income dealt with in Article 12 (Royalties and Fees for Included Services). The rules of this paragraph shall not apply in determining credits against United States tax for foreign taxes other than the taxes referred to in paragraph (1b) and 2 of Article 2 (Taxes Covered).

ARTICLE 26

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Except where the provisions of paragraph 3 of Article 7 (Business Profits) apply, the taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs, and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9 (Associated Enterprises), paragraph 7 of Article 11 (Interest), or paragraph 8 of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) apply, interest, royalties, and other disbursements paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable profits of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. Nothing in this article shall be construed as preventing either Contracting State from imposing the taxes described in Article 14 (Permanent Establishment Tax) or the limitations described in paragraph 3 of Article 7 (Business Profits).

ARTICLE 27

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this convention, he may, irrespective

of the remedies provided by the domestic law of those State, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or national. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities, through consultations, shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article. In addition, a competent authority may devise appropriate unilateral procedures, conditions, methods and techniques to facilitate the abovementioned bilateral actions and the implementation of the mutual agreement procedure.

ARTICLE 28

Exchange of Information and Administrative Assistance

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the convention, in particular, for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1 (General Scope). Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that state. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting state, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment, collection, or administration of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes, but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through

consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases, or otherwise. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial, or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the Article, the other Contracting State shall obtain the information to which the request relates in the same manner and in the same form as if the tax of the first-mentioned State were the tax of that other State and were being imposed by that other State. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall provide information under this Article in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts, and writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

5. For the purposes of this Article, the Convention shall apply, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes Covered) :

- (a) in the United States, to all taxes imposed under Title 26 of the United States Code; and
- (b) in India, to the income tax, the wealth tax and the gift tax.

ARTICLE 29

Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 30

Entry Into Force

1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State in writing, through diplomatic channels, upon the completion of their respective legal procedures to bring this Convention into force.

2. The Convention shall enter into force on the date of the latter of such notifications and its provisions shall have effect:

(a) in the United States

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force; and

(b) in India, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force.

ARTICLE 31

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of the entry into force of the Convention, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and in such event, this Convention shall cease to have effect:

(a) in the United States

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January next following the calendar year in which notice of termination is given; and

(ii) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given; and

(b) in India, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE at New Delhi in duplicate, this 12th day of September, 1989, in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA:

N. K. Sengupta

Secretary to the
Government of India

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:

John R. Hubbard
Ambassador

PROTOCOL

At the signing today of the Convention between the Republic of India and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions, which shall form an integral part of the Convention:

I. Ad Article 5

It is understood that where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State in accordance with the provisions of paragraphs 2(j), 2(k) or 2(l) of Article 5 (Permanent Establishment), and the time period referred to in that paragraph extends over two taxable years, a permanent establishment shall not be deemed to exist in a year, if any, in which the use, site, project or activity, as the case may be, continues for a period or periods aggregating less than 30 days in that taxable year. A permanent establishment will exist in the other taxable year, and the enterprise will be subject to tax in that other Contracting State in accordance with the provisions of Article 7 (Business Profits), but only on income arising during that other taxable year.

II. Ad Article 7

Where the law of the Contracting State in which a permanent establishment is situated imposes, in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 7 (Business Profits), a restriction on the amount of executive and general administrative expenses which may be allowed as a deduction in determining the profits of such permanent establishment, it is understood that in making such a determination of profits the deduction in respect of such executive and general administrative expenses in no case shall be less than that allowable under the Indian Income-tax Act as on the date of signature of this Convention.

III. All Articles 7, 10, 11, 12, 15 and 23

It is understood that for the implementation of paragraphs 1 and 2 of Article 7 (Business Profits), paragraph 4 of Article 10 (Dividends), paragraph 5

of Article 11 (Interest), paragraph 6 of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services), paragraph 1 of Article 15 (Independent Personal Services), and paragraph 2 of Article 23 (Other Income), any income attributable to a permanent establishment or fixed base during its existence is taxable in the Contracting State in which such permanent establishment or fixed base is situated even if the payments are deferred until such permanent establishment or fixed base has ceased to exist.

IV. Ad Article 12

It is understood that fees for included services, as defined in paragraph 4 of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) will, accordance with United States law, be subject to Income tax in the United States based on net income and, when earned by a company, will also be subject to the taxes described in paragraph 1 of Article (Permanent Establishment Tax). The total of these taxes which may be imposed on such fees, however, may not exceed the amount computed by multiplying the gross fee by the appropriate tax rate specified in sub paragraph (a) or (b), whichever is applicable, of paragraph 2 of Article 12.

V. Ad Article 14

It is understood that references in paragraph 1 of Article 14 (Permanent Establishment tax) to profits that are subject to tax in the United States under Article 6 (Income from Immovable Property (Real Property)), under Article 12 (Royalties and Fees for Included Services), as fees for included services as defined in that Article, or under Article 13 (Gains) of this Convention, are intended to refer only to cases in which the profits in question are subject to United States tax based on net income (i.e., by virtue of being effectively connected, or being treated as effectively connected, with the conduct of a trade or business in the United States). Any income which is subject to tax under those Article based on gross income is not subject to tax under Article 14.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE at New Delhi in duplicate, this 12th day of September, 1989, in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA :

N. K. Sengupta,
Secretary to the
Government of India

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA :

John R. Hubbard
Ambassador.

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

New Delhi, September 12, 1989

Excellency :

I have the honour to refer to the Convention between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income which was signed today (hereinafter referred to as "the Convention") and to confirm, on behalf of the Government of the United States of America, the following understandings reached between the two Governments;

Both sides agree that a tax sparing credit shall not be provided in Article 25 (Relief from Double Taxation) of the Convention at this time. However, the Convention shall be promptly amended to incorporate a tax sparing credit provision if the United States hereafter amends its laws concerning the provision of tax sparing credits, and the United States reaches agreement on the provision of a tax sparing credit with any other country.

Both sides also agree that, for purposes of paragraph 4(c) of Article 5 (Permanent Establishment) of the Convention, a person shall be considered to habitually secure orders in a Contracting State, wholly or almost wholly for an enterprise, only if :

1. such person frequently accepts orders for goods or merchandise on behalf of the enterprise;
2. substantially all of such person's sales-related activities in the Contracting State consist of activities for the enterprise;
3. such person habitually represents to persons offering to buy goods or merchandise that acceptance of an order by such person constitutes the agreement of the enterprise to supply goods or merchandise under the terms and conditions specified in the order; and
4. the enterprise takes actions that give purchasers the basis for a reasonable belief that such person has authority to bind the enterprise.

I have the honour to request Your Excellency to confirm the foregoing understandings of Your Excellency's Government.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

His Excellency

Dr. N. K. Sengupta,
Secretary (Revenue),
Ministry of Finance,
New Delhi.

Sd/-

John R. Hubbard
Ambassador.

SECRETARY

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 12th September, 1989

Excellency :

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Convention between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income which was signed today (hereinafter referred to as "the Convention") and to confirm, on behalf of the Government of the United States of America, the following understandings reached between the two Governments:

Both sides agree that a tax sparing credit shall not be provided in Article 25 (Relief from Double Taxation) of the Convention at this time. However, the Convention shall be promptly amended to incorporate a tax sparing credit provision if the United States hereafter amends its laws concerning the provision of tax sparing credits, or the United States reaches agreement on the provision of a tax sparing credit with any other country.

Both sides also agree that, for purposes of paragraph 4(c) of Article 5 (Permanent Establishment) of the Convention, a person shall be considered to habitually secure orders in a Contracting State, wholly or almost wholly for an enterprise, only if:

1. such person frequently accepts orders for goods or merchandise on behalf of the enterprise;
2. substantially all of such person's sales-related activities in the Contracting State consist of activities for the enterprise;
3. such person habitually represents to persons offering to buy goods or merchandise that acceptance of an order by such person constitutes the agreement of the enterprise to supply goods or merchandise under the terms and conditions specified in the order; and
4. the enterprise takes actions that give purchasers the basis for at reasonable belief that such person has authority to bind the enterprise."

I have the honour to confirm the understandings contained in Your Excellency's Note, on behalf of the Government of the Republic of India.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

His Excellency
Dr. John R. Hubbard,
Ambassador of the
United States of America,
New Delhi.

Sd/-

N. K. Sengupta.

EMBASSY OF THE

UNITED STATES OF AMERICA

New Delhi, the 12th September, 1989

Excellency :

I have the honour to refer to the Convention signed today between the United States of America and the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and to inform you on behalf of the United States of America of the following:

During the course of the negotiations leading to conclusion of the Convention signed today, the negotiators developed and agreed upon a memorandum of understanding intended to give guidance both to the taxpayers and the tax authorities of our two countries in interpreting aspects of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) relating to the scope of included services. This memorandum of understanding represents the current views of the United States Government with respect to these aspects of Article 12, and it is my Government's understanding that it also represents the current views of the Indian Government. It is also my Government's view that as our Governments gain experience in administering the Convention, and particularly Article 12, the competent authorities may develop and publish amendments to the memorandum of understanding and further understandings and interpretations of the Convention.

If this position meets with the approval of the Government of the Republic of India, this letter and your reply thereto will indicate that our Governments share a common view of the purpose of the memorandum of understanding relating to Article 12 of the Convention.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

His Excellency
Dr. N. K. Sengupta,
Secretary (Revenue),
Ministry of Finance,
New Delhi.

Sd/-

John R. Hubbard
Ambassador

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 12th September, 1989

Excellency :

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows :

"I have the honour to refer to the Convention signed today between the United States of America and the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on income and to inform you on behalf of the United States of America of the following :

During the course of the negotiations leading to conclusion of the Convention signed today, the negotiators developed and agreed upon a memorandum of understanding intended to give guidance both to the taxpayers and the tax authorities of our two countries in interpreting aspects of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) relating to the scope of included services. This memorandum of understanding represents the current views of the United States Government with respect to these aspects of Article 12, and it is my Government's understanding that it also represents the current views of the Indian Government. It is also my Government's view that as our Governments gain experience in administering the Convention, and particularly Article 12, the competent authorities may develop and publish amendments to the memorandum of understanding and further understandings and interpretations of the Convention.

If this position meets with the approval of the Government of the Republic of India this letter and your reply thereto will indicate that our Governments share a common view of the purpose of the memorandum of understanding relating to Article 12 of the Convention."

I have the honour to confirm the understandings contained in Your Excellency's Note, on behalf of the Government of the Republic of India.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

His Excellency
Dr. John R. Hubbard,
Ambassador of the
United States of America,
New Delhi.

Sd/-
N. K. Sengupta

May 15, 1989

U.S.—INDIA TAX TREATY

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING FEES FOR INCLUDED SERVICES IN

ARTICLE 12

Paragraph 4 (in general)

This memorandum described in some detail the category of services defined in paragraph 4 of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services). It also provides examples of services intended to be covered within the definition of included services and those intended to be excluded, either because they do not satisfy the tests of paragraph 4, or because, notwithstanding the fact that they meet the tests of paragraph 4, they are dealt with under paragraph 5. The examples in either case are not intended as an exhaustive list but rather as illustrating a few typical cases. For ease of understanding, the examples in this memorandum describe U.S. persons providing services to Indian persons, but the rules of Article 12 are reciprocal in application.

Article 12 includes only certain technical and consultancy services. By technical services, we mean in this context services requiring expertise in a technology. By consultancy services, we mean in this context advisory services. The categories of technical and consultancy services are to some extent overlapping because a consultancy service could also be a technical service. However, the category of consultancy services also includes an advisory service, whether or not expertise in a technology is required to perform it.

Under paragraph 4, technical and consultancy services are considered included services only to the following extent: (1) as described in paragraph 4(a), if they are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of a right, property or information for which a royalty payment is made; or (2) as described in paragraph 4(b), if they make available technical knowledge, experience, skill, know-how, or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design. Thus, under paragraph 4(b), consultancy services which are not of a technical nature cannot be included services.

Paragraph 4(a)

Paragraph 4(a) of Article 12 refers to technical or consultancy services that are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of any right, property, or information for which a payment described in paragraph 3(a) or (b) is received. Thus, paragraph 4(a) includes technical and consultancy services that are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of an intangible for which a royalty is received under a license or sale as described in paragraph 3(a), as well as those ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of industrial, commercial, or scientific equipment for which a royalty is received under a lease as described in paragraph 3(b).

It is understood that, in order for a service fee will be considered "ancillary and subsidiary" to the application or enjoyment of some right, property, or information for which a payment described in paragraph

3(a) or (b) is received, the service must be related to the application or enjoyment of the right, property, or information. In addition, the clearly predominant purpose of the arrangement under which the payment of the service fee and such other payment are made must be the application or enjoyment of the right, property, or information described in paragraph 3. The question of whether the service is related to the application or enjoyment of the right, property, or information described in paragraph 3 and whether the clearly predominant purpose of the arrangement is such application or enjoyment must be determined by reference to the facts and circumstances of each case. Factors which may be relevant to such determination (although not necessarily controlling) include :

1. the extent to which the services in question facilitate the effective application or enjoyment of the right, property, or information described in paragraph 3;
2. the extent to which such services are customarily provided in the ordinary course of business arrangements involving royalties described in paragraph 3;
3. whether the amount paid for the services (or which would be paid by parties operating at arm's length) is an insubstantial portion of the combined payments for the services and the right, property, or information described in paragraph 3;
4. whether the payment made for the services and the royalty described in paragraph 3 are made under a single contract (or a set of related contracts); and
5. whether the person performing the services is the same person as, or a related person to, the person receiving the royalties described in paragraph 3 for this purpose, persons are considered related if their relationship is described in Article 9 (Associated Enterprises) or if the person providing the service is doing so in connection with an overall arrangement which includes the payor and recipient of the royalties).

To the extent that services are not considered ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of some right, property, or information for which a royalty payment under paragraph 3 is made, such services shall be considered "included services" only to the extent that they are described in paragraph 4(b).

Example (1)

Facts :

A U.S. manufacturer grants rights to an Indian company to use manufacturing processes in which the transferor has exclusive rights by virtue of process patents or the protection otherwise extended by law to the owner of a process. As part of the contractual arrangement, the U. S. manufacturer agrees to provide certain consultancy services to the Indian company in order to improve the

effectiveness of the latter's use of the processes. Such services include, for example, the provision of information and advice on sources of supply for materials needed in the manufacturing process, and on the development of sales and service literature for the manufactured product. The payments allocable to such services do not form a substantial part of the total consideration payable under the contractual arrangement. Are the payments for these services fees for "included services" ?

Analysis :

The payments are fees for included services. The services described in this example are ancillary and subsidiary to the use of a manufacturing process protected by law as described in paragraph 3(a) of Article 12 because the services are related to the application or enjoyment of the intangible and the granting of the right to use the intangible is the clearly predominant purpose of the arrangement. Because the services are ancillary and subsidiary to the use of the manufacturing process, the fees for these services are considered fees for included services under paragraph 4(a) of Article 12, regardless of whether the services are described in paragraph 4(b).

Example (2)

Facts :

An Indian manufacturing company produces a product that must be manufactured under sterile conditions using machinery that must be kept completely free of bacterial or other harmful deposits. A U.S. company has developed a special cleaning process for removing such deposits from that type of machinery. The U.S. company enters into a contract with the Indian company under which the former will clean the latter's machinery on a regular basis. As part of the arrangement, the U.S. company leases to the Indian company a piece of equipment which allows the Indian company to measure the level of bacterial deposits on its machinery in order for it to know when cleaning is required. Are the payments for the services fees for included services ?

Analysis :

In this example, the provision of cleaning services by the U.S. company and the rental of the monitoring equipment are related to each other. However, the clearly predominant purpose of the arrangement is the provision of cleaning services. Thus, although the cleaning services might be considered technical services, they are not "ancillary and subsidiary" to the rental of the monitoring equipment. Accordingly, the cleaning services are not "included services" within the meaning of paragraph 4(a).

Paragraph 4(b) :

Paragraph 4(b) of Article 12 refers to technical or consultancy services that make available to the person acquiring the service technical knowledge, experience, skill, know-how, or processes, or consist at the development and transfer of a technical plan or technical design to such person. (For this purpose, the person acquiring the service shall be deemed to include an agent nominee, or transferee of such person.) This category is narrower than the category described in paragraph 4(a) because it excludes any service that does not make technology available to the person acquiring the service. Generally speaking, technology will be considered "made available" when the person acquiring the service is enabled to apply the technology. The fact that the provision of the service may require technical input by the person providing the service does not per se mean that technical knowledge, skills, etc. are made available to the person purchasing the service, within the meaning of paragraph 4(b). Similarly, the use of a product which embodies technology shall not per se be considered to make the technology available.

Typical categories of services that generally involve either the development and transfer of technical plans or technical designs, or making technology available as described in paragraph 4(b), include :

1. engineering services (including the subcategories of bioengineering and aeronautical, agricultural, ceramics, chemical, civil, electrical, mechanical, metallurgical, and industrial engineering);
2. architectural services; and
3. computer software development.

Under paragraph 4(b), technical and consultancy services could make technology available in a variety of settings, activities and industries. Such services may, for example, relate to any of the following areas :

1. bio-technical services;
2. food processing ;
3. environmental and ecological services;
4. communication through satellite or otherwise;
5. energy conservation;
6. exploration or exploitation of mineral oil or natural gas;
7. geological surveys;
8. scientific services; and
9. technical training.

The following examples indicate the scope of the conditions in paragraph 4(b):

Example (3)**Facts :**

- A U.S. manufacturer has experience in the use of a process for manufacturing wallboard for

interior walls of houses which is more durable than the standard products of its type. An Indian builder wishes to produce this product for its own use. It rents a plant and contracts with the U.S. company to send experts to India to show engineers in the Indian company how to produce the extra-strong wallboard. The U.S. contractors work with the technicians in the Indian firm for a few months. Are the payments to the U.S. firm considered to be payments for "included services"?

Analysis :

The payments would be fees for included services. The services are of a technical or consultancy nature; in the example, they have elements of both types of services. The services make available to the Indian company technical knowledge, skill, and processes.

Example (4)**Facts :**

- A U.S. manufacturer operates a wallboard fabrication plant outside India. An Indian builder hires the U.S. company to produce wallboard at that plant for a fee. The Indian company provides the raw materials, and the U.S. manufacturer fabricates the wallboard in its plant, using advanced technology. Are the fees in this example payments for included services?

Analysis :

The fees would not be for included services. Although the U.S. company is clearly performing a technical service, no technical knowledge, skill, etc., are made available to the Indian company, nor is there any development and transfer of a technical plan or design. The U.S. company is merely performing a contract manufacturing service.

Example (5)**Facts :**

- An Indian firm owns inventory control software for use in its chain of retail outlets throughout India. It expands its sales operation by employing a team of travelling salesmen to travel around the countryside selling the company's wares. The company wants to modify its software to permit the salesman to access the company's central computers for information on what products are available in inventory and when they can be delivered. The Indian firm hires a U.S. computer programming firm to modify its software for this purpose. Are the fees which the Indian firm pays treated as fees for included services?

Analysis :

The fees are for included services. The U.S. company clearly performs a technical service for the Indian company, and it transfers to

the Indian company the technical plan (i.e., the computer program) which it has developed.

Example (6)

Facts :

An Indian vegetable oil manufacturing company wants to produce a cholesterol-free oil from a plant which produces oil normally containing cholesterol. An American company has developed a process for refining the cholesterol out of the Oil. The Indian company contracts with the U.S. company to modify the formulas which it uses so as to eliminate the cholesterol, and to train the employees of the Indian company in applying the new formulas. Are the fees paid by the Indian company for included services?

Analysis :

The fees are for included services. The services are technical, and the technical knowledge is made available to the Indian company.

Example (7)

Facts :

The Indian vegetable oil manufacturing firm has mastered the science of producing cholesterol-free oil and wishes to market the product world-wide. It hires an American marketing consulting firm to do a computer simulation of the world market for such oil and to advise it on marketing strategies. Are the fees paid to the U.S. company for included services?

Analysis :

The fees would not be for included services. The American company is providing a consultancy service which involves the use of substantial technical skill and expertise. It is not, however, making available to the Indian company and technical experience, knowledge or skill, etc. nor is it transferring a technical plan or design. What is transferred to the Indian company through the service contract is commercial information. The fact that technical skills were required by the performer of the service in order to perform the commercial information service does not make the service a technical service within the meaning of paragraph 4(b).

Paragraph 5

Paragraph 5 of Article 12 describes several categories of services which are not intended to be treated as included services even if they satisfy the tests of paragraph 4. Set forth below are examples of cases where fees would be included under paragraph 4, but are excluded because of the conditions of paragraph 5.

Example (8)

Facts :

An Indian company purchases a computer from a U.S. computer manufacturer. As part of the purchase agreement, the manufacturer agrees to assist the Indian company in setting up the computer and installing the operating system, and to ensure that the staff of the Indian company is able to operate the computer. Also, as part of the purchase agreement, the seller agrees to provide, for a period of ten years, any updates to the operating system and any training necessary to apply the update. Both of these service elements to the contract would qualify under paragraph 4(b) as an included service. Would either or both be excluded from the category of included services, under paragraph 5(a), because they are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of the computer?

Analysis :

The installation assistance and initial training are ancillary and subsidiary to the sale of the computer, and they are also inextricably and essentially linked to the sale. The computer would be of little value to the Indian purchaser without these services, which are most readily and usefully provided by the seller. The fees for installation assistance and initial training, therefore, are not fees for included services, since these services are not the predominant purpose of the arrangement.

The services of updating the operating system and providing associated necessary training may well be ancillary and subsidiary to the sale of computer, but they are not inextricably and essentially linked to the sale. Without the upgrades, the computer will continue to operate as it did when purchased, and will continue to accomplish the same functions. Acquiring the updates cannot, therefore, be said to be inextricably and essentially linked to the sale of the computer.

Example (9)

Facts :

An Indian hospital purchases an X-ray machine from a U.S. manufacturer. As part of the purchase agreement, the manufacturer agrees to install the machine, to perform an initial inspection of the machine in India, to train hospital staff in the use of the

machine, and to service the machine periodically during the usual warranty period (2 years). Under an optional service contract purchased by the hospital, the manufacturer also agrees to perform certain other services throughout the life of the machine, including periodic inspections and repair services, advising the hospital about developments in X-ray film or techniques which could improve the effectiveness of the machine, and training hospital staff in the application of those new developments. The cost of the initial installation, inspection, training, and warranty service is relatively minor as compared with the cost of the X-ray machine. Is any of the service described here ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of the X-ray machine?

Analysis :

The initial installation, inspection, and training services in India and the periodic service during the warranty period are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of the X-ray machine because the usefulness of the machine to the hospital depends on this service, the manufacturer has full responsibility during this period, and the cost of the services is a relatively minor component of the contract. Therefore, under paragraph 5(a) these fees are not fees for included services, regardless of whether they otherwise would fall within paragraph 4(b).

Neither the post-warranty period inspection and repair services, nor the advisory and training services relating to new developments are "inextricably and essentially linked" to the initial purchase of the X-ray machine. Accordingly, fees for these services may be treated as fees included services if they meet the tests of paragraph 4(b).

Example (10)

Facts :

An Indian automobile manufacturer decides to expand into the manufacture of helicopters. It sends a group of engineers from its design staff to a course of study conducted by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for two years to study aeronautical engineering. The Indian firm pays tuition fees to MIT on behalf of the firm's employees. Is the tuition fee a fee for an included service within the meaning of Article 12?

Analysis :

The tuition fee is clearly intended to acquire a technical service for the firm. However, the fee paid is for teaching by an educational institution, and is, therefore, under paragraph 5(c), not an included service. It is irrelevant for this purpose whether MIT conducts the course on its campus or at some other location.

Example (11)

Facts :

As in Example (10), the automobile manufacturer wishes to expend into the manufacture of helicopters. It approaches an Indian university about establishing a course of study in aeronautical engineering. The university contracts with a U.S. helicopter manufacturer to send an engineer to be a visiting professor of aeronautical engineering on its faculty for a year. Are the amounts paid by the university for these teaching services fees for included services?

Analysis :

The fees are for teaching in an educational institution. As such, pursuant to paragraph 5(c), they are not fees for included services.

Example (12)

Facts :

An Indian wishes to install a computerized system in his home to control lighting, heating and air conditioning, a stereo sound system and a burglar and fire alarm system. He hires an American electrical engineering firm to design the necessary wiring system, adapt standard software, and provide instructions for installations. Are the fees paid to the American firm by the Indian individual fees for included services?

Analysis :

The services in respect of which the fees are paid are of the type which would generally be treated as fees for included services under paragraph 4(b). However, because the services are for the personal use of the individual making the payment, under paragraph 5(d) the payments would not be fees for included services.

[Notification No. 8786 (F.No. 501)2/74-FTD)]

N. C. JAIN, Jt. Secy.